राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

सबसे बड़ी खबर

भव्य खबर

RNI No.- DELHIN/2016/68043

नई दिल्ली संस्करण, नई दिल्ली, गुरुवार, 17 अप्रैल 2025, वर्ष : 9, अंक : 21 पृष्ठ : 08, मूल्य : 02 रुपया

नई दिल्ली से प्रकाशित व दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसारित

पेज :2

पेज : 2

छत्तीसगढ़ में सुबह-सुबह हुई ठांय-ठांय, सुरक्षाबलों ने मार गिराए दो हार्डकोर नक्सली

कोंडागांव। जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं। दोनों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पूर्वी बस्तर डिवीजन के डिविजनल कमेटी सदस्य हलदर पर आठ लाख रुपए और एरिया कमेटी सदस्य रामे पर पांच लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा में स्थित किलम -बरगुम क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर कोंडागांव 'जिला रिजर्व गार्ड' और 'बस्तर फाइटर्स' के दल को मंगलवार को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान मंगलवार देर शाम सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक और नक्सली सामान बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है इससे पहले मंगलवार को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पांच लाख रुपये के इनाम नक्सली ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में 34 साल के रूपेश मंडावी उर्फ सुखदेव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि नक्सली ने माओवादियों की 'खोखली' और 'अमानवीय विचारधारा तथा नक्सली संगठन के भीतर बढ़ते मतभेदों से निराश होकर तथा राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है।

पैसे देकर बाहरी लोगों को बुलाया, बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार

सीएम ममता ने कहा- कई जगह वक्फ संपत्तियों पर हिंदू परिवार भी रहते हैं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में भड़की हिंसा के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पैसा देकर बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों में हिंदुओं को सोशल वेलफेयर के लिए वक्फ ने दान दिया है। आज कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों पर हिंदू परिवार रहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ने और उसका नियंत्रण आपने हाथों में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आपकी सिंगल मैजोरिटी नहीं है, फिर यह कैसे कर रहे हैं?

उन्होंने बीजेपी के मनमानी के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा कि आप दोनों क्यों चुप हैं? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दिया? अगर वक्फ में बदलाव करना था, तो संविधान संशोधन क्यों नहीं किया? आपने चालाकी से बिल पास कराया। ममता ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रामनवमी के दिन दंगे भड़काने की योजना बनाई थी, लेकिन जनता ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि हर समाज में कुछ गद्दार होते हैं जो पैसे लेकर अपनी ही जड़ें काटते हैं। अगर आपको विरोध करना है, तो इंडोर स्टेडियम में करें, बाहर नहीं, क्योंकि वहां बीजेपी वाले हिंदू-मुस्लिम तनाव भड़काएंगे। ममता ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? बांग्लादेश की स्थिति का क्या पता? आप यूनुस के साथ चुपके-चुपके बैठक करते हैं, आपका योजना क्या है? उन्होंने शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कभी पीएम नहीं बनेंगे। मोदीजी जब पीएम नहीं रहेंगे, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। मोदीजी से कहूंगी कि इस व्यक्ति को नियंत्रित करें, जो सभी एजेंसियों को अपने कब्जे में रखे हुए है। भड़की हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित सांप्रदायिक दंगे हैं।

उर्दू भारत में ही जन्मी भाषा, इसे किसी धर्म से जोड़ना है गलत

-सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, याचिका को किया खारिज

अकोला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भाषा संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने उर्दू को गंगा-जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल बताते हुए इसे भारत में जन्मी भाषा करार दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पातुर नगर परिषद की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की भाषाई विविधता की सराहना की और कहा कि हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागकर हर भाषा से दोस्ती करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भारत का विभाजन न हुआ होता, तो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी शायद देश की राष्ट्रीय भाषा होती। याचिकाकर्ता ने साइनबोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को चुनौती दी थी और दावा किया था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम, 2022 के तहत केवल मराठी का इस्तेमाल होना चाहिए। पीठ ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया ने कहा कि उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। यह गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जो उत्तरी और मध्य भारत की समन्वित सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उन्होंने साफ कहा कि उर्दू और मराठी दोनों का संविधान के तहत समान दर्जा है। कोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय लोग उर्दू से परिचित हैं, तो साइनबोर्ड पर इसका इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू को अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है।

ऐसे तो वक्फ बोर्ड पर कब्जा हो जाएगा मीलॉर्ड

- कलेक्टर की पावर, हिंदुओं की एंट्री पर बरसे कपिल सिब्बल

कहा-वक्फ पर हिंदुओं की एंट्री आर्टिकल 26 का उल्लंघन

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने ऐक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कर दी गई है, यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वायत्तता देता है। अब नया वक्फ ऐक्ट उस स्वायत्तता को छीनने वाला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं की भी इनमें एंट्री होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी

दिक्कत क्या है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार छीनने जैसा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुल 2 पदेन सदस्य ही गैर-मुसलमान हो सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा,नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

300 साल पुरानी संपत्ति की भी मांगेंगे वक्फ डीड कहां से लाएंगे

सीनियर वकील ने यह भी कहा कि नया ऐक्ट कहते हैं कि किसी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा, जब उसकी वक्फ डीड हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि परेशानी क्या है। सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर की अवधारणा है। मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति है और मेरे कोई संतान नहीं है। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से तो हेल्प ही मिलेगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर तो अब खत्म कर दिया गया है। अयोध्या के फैसले से यह पता चलता है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों को रोकने के लिए वक्फ डीड की बात कही गई है। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। वक्फ की संपत्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। वे तो 300 साल पुरानी संपत्ति की भी वक्फ डीड मांग लेंगे।

शिवराज चौहान ने ब्राजील के कृषि व्यापार समुदाय के सदस्यों से किया विचार-विमर्श

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील के दौरे पर हैं। आज उन्होंने साओ पाउलो में ब्राजील के कृषि व्यापार समुदाय के सदस्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण और बायो फ्यूल आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर जानकारी दी कि ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचा हूं। इस दौरान आज साओ पाउलो में ब्राजील के कृषि व्यापार समुदाय के सदस्यों से संवाद हुआ। इस दौरान कृषि व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, बायोफ्यूल, बायोएनर्जी, तकनीकी नवाचार व आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों से न केवल हमारे किसान सशक्त तथा समृद्ध होंगे, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी नई दिशा मिलेगी।

कांग्रेस ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोपपत्र को लेकर प्रदर्शन किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने के विरोध में बुधवार को यहां प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बुधवार को सुबह ही पार्टी के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंच गए और अपने नेताओं के पक्ष और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति से प्रेरित मामला है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'यह राजनीति से प्रेरित मामला है। हमें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है। हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।' पायलट ने कहा कि यह सब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया गया हैद्य

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया, 'नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से 1947 से पहले अंग्रेज़ चिढ़ते थे, आज 2025 में आरएसएस के लोग चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी तब भी मज़लूमों की आवाज़ थी और आज भी है। खेड़ा ने कहा, 'जिस गैर लाभकारी कंपनी में एक रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ, कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, उस पर धन शोधन का मामला दर्ज करना मोदी के डर का परिचायक है।'

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोप-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की।

पीएम मोदी का जम्मू-कश्मीर दौरा स्थगित, मौसम को बताया वजह

19 को कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाने वाले थे हरी झंडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर यात्रा स्थगित हो गई है। इस दौरे में पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला खराब मौसम की चेतावनी बताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के श्रीनगर कार्यालय ने 18 और 19 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

पीएम के दौरे को लेकर राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लाइन पर पहले ही मॉक ड्रिल और ट्रायल रन किया जा चुका है।

मंगलवार को इस खंड पर ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए थे। विशेष सतर्कता कठुआ, उधमपुर, रियासी और रामबन जिलों में बरती जा रही थी। इसके अलावा पुंछ जिले के लस्साना के जंगलों में भी तलाशी अभियान जारी है।

कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें पीएम मोदी की यात्रा और आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा के दौरान दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें- एक श्रीनगर से कटरा और दूसरी कटरा से श्रीनगर तक चलाने की योजना थी। ये ट्रेनें उद्घाटन के दिन से शुरू होनी थीं। अब पीएम मोदी की यात्रा स्थगित हो गई है, तो उद्घाटन कार्यक्रम की नई तारीख का इंतजार है।

सूत्रों के मुताबिक मौसम अनुकूल होने के बाद पीएम मोदी का दौरा फिर तय किया जाएगा। गौरतलब है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जनवरी में कटरा और कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा को मंजूरी दी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इस क्षेत्र के लिए आधुनिक एवं कुशल रेल सेवा उपलब्ध होगी। इस ऐतिहासिक ट्रेन सेवा के शुरू होने के साथ ही कश्मीर तक सीधी रेल संपर्क सुविधा की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो जाएगी। वर्तमान में घाटी में केवल संगलदान एवं बारामूला के बीच और कटरा से देश भर के गंतव्यों के लिए ट्रेन चलती हैं।

जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस

- 14 मई से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम,संजीव खन्ना ने की सिफारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है।

हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के

रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवई लगभग छह महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस गवई नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद वे चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रोमोट किया गया था। जस्टिस गवई राज्य में हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। उसके बाद, उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की। जस्टिस गवई अगस्त 1992 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया गया।

ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर किया 245 प्रतिशत

-5 दिन पहले अमेरिकी सामान पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया था

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर और आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने अब चीन पर 100 प्रतिशत और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245 प्रतिशत हो गया है।

चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रम्प ने नया टैरिफ लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा।

अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से नहीं डरते

अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अगर अमेरिका सच में बातचीत को डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है, तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। लिन जियान ने पत्रकारों से कहा कि 245 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ

के तहत अलग-अलग टैक्स रेट क्या होगा ये आप अमेरिका से ही पूछिए। ये टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू किया है, हमने नहीं। हम सिर्फ अमेरिका के एक्शन का जवाब दे रहे हैं। हमारे कदम पूरी तरह तार्किक और कानूनी हैं। हम अपने देश के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन पर सख्ती का अमेरिका ने बताया यह कारण

ट्रंप प्रशासन के दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने कुछ महीने पहले अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य प्रमुख उच्च-तकनीकी सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनके सैन्य उपयोग की संभावना थी। इसी सप्ताह चीन छह भारी दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल के साथ-साथ रेयर अर्थ चुंबकों के निर्यात को भी निर्लंबित कर दिया था। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया भर में ऑटोमेकर्स, एयरोस्पेस निर्माताओं, सेमीकंडक्टर कंपनियों और सैन्य ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति रोकने के लिए की गई।

अमेरिका के 245 प्रतिशत टैरिफ पर चीन ने दी यह प्रतिक्रिया

चीन ने अमेरिका की आरे से लगाए गए 245 प्रतिशत टैरिफ पर पर प्रतिक्रिया देते हुए कि कहा कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ के आंकड़ों का स्पष्ट ब्यौरा दे। चीन के आयात पर अमेरिका ने 245 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का एलान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिकी पक्ष को विशिष्ट कर दर के आंकड़े के बारे में बताना चाहिए। बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, लिन ने कहा कि चीन ने टैरिफ मुद्दे पर अपनी स्थिति को बार-बार साफ किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ युद्ध अमेरिका की ओर से शुरू किया गया था और बीजिंग ने अपने वैध अधिकारों और हितों और अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाए हैं। ये कदम पूरी तरह से उचित और कानूनी हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ और व्यापार युद्धों में कोई विजेता नहीं होता है। उन्होंने कहा कि चीन इन युद्धों को लडना नहीं चाहता है, लेकिन इनसे डरता भी नहीं है। उन्होंने हाथ मिलाने और बाधाओं को दूर करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नड्डा के घर सीक्रेट बैठक, पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात.. क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी में सरकार

-सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में इन दिनों नए वक्फ कानून को लेकर राजनीति जारी है। संसद से पारित नए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की आग में जहां एक ओर पश्चिम बंगाल के कई इलाके हिंसा की आग में जल रहे हैं। वहीं कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरु हो गई। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की हालिया गतिविधि ने सभी का ध्यान खींचा है। अटकलें है कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है।

दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बीती रात एक हाई-प्रोफाइल बैठक ने इन बातों को हवा दी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शाह और सिंह जैसे नेताओं की मौजूदगी इसका संकेत देती है कि चर्चा में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव का होना आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े मसलों की ओर इशारा करता है। कुछ जानकारों का कहना है कि बैठक मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की संभावना को भी बल दे रही है। इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात भी करीब एक घंटे तक चली। हालांकि, मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है। कुछ का मानना है कि यह एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन नड्डा के आवास पर चल रही बैठक के साथ इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मुलाकात किसी बड़े संवैधानिक या प्रशासनिक फैसले से जुड़ी है? क्या मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है?

भाजपा व डीएमके का साथ जीत ग्यारंटी बनेगा ?

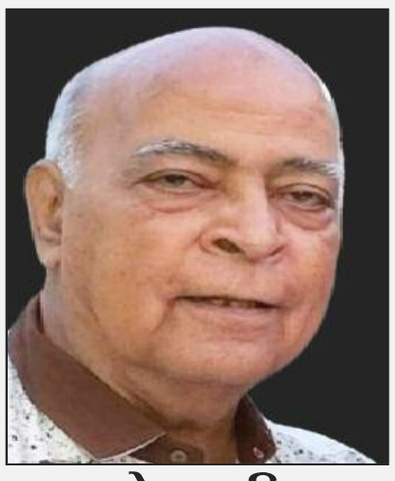

अशोक भाटिया

लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर एक हंगामेदार बहस हुई। विधेयक का विरोध करने के लिए भाजपा का विपक्ष एक साथ आया था। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस,डीएमके सहित विपक्षी दल। एआईएडीएमके ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। इतना ही नहीं एआईएडीएमके के सांसदों ने राज्यसभा में भी वक्फ सुधार सरकार के खिलाफ वोट किया था। तो अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों ही बहुत करीब आ गए ?

4 अप्रैल को तमिल नववर्ष से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ राज्य में गठबंधन बनाने की घोषणा की। हालाँकि एआईएडीएमके ने एक समय तमिलनाडु के द्रविड़-प्रभुत्व वाले राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इसका वही प्रभाव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री जे। जयललिता के समय था।पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के। पलानीस्वामी (ईपीएस) की अगुआई वाली पार्टी अपने पार्टी सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ। पनीरसेल्वम (ओपीएस) के साथ नियंत्रण के लिए तीखे संघर्ष के बाद सत्ता में बनी हुई है। 2016 से 2021 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से जुड़े रहने के कारण, ईपीएस ने भाजपा नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध का आनंद लिया। पिछले हफ़्ते चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा में भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि ईपीएस मौजूदा एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके गठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है और सत्र के अंत में, लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर एक हंगामेदार बहस हुई। विधेयक का विरोध करने के लिए भाजपा का विपक्ष एक साथ आया था। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस,डीएमके सहित विपक्षी दल। एआईएडीएमके ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। इतना ही नहीं एआईएडीएमके के सांसदों ने राज्यसभा में भी वक्फ सुधार सरकार के खिलाफ वोट किया था। तो अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों ही बहुत करीब आ गए? अमित शाह एक राजनयिक राजनेता हैं और राजनीतिक कूटनीति में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। एक राजनीतिक दल जो संसद में भाजपा का समर्थन नहीं करता है, वह राजनीतिक दल जिसने पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, एआईएडीएमके, वह पार्टी जिसने एनडीए में फिर से प्रवेश किया। ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि इसने देश के सभी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एआईएडीएमके पार्टी के साथ जल्दबाजी में गठबंधन क्यों किया गया, इसका रहस्य कई लोगों के सामने नहीं आया है। इससे पहले, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी, और अब भाजपा अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन करके चेन्नई के सिंहासन से एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा पिछले 10-12 वर्षों से तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने महसूस किया है कि द्रमुक बनाम अन्नाद्रमुक की लड़ाई में भाजपा का कोई लाभ नहीं है। भाजपा और एआईएडीएमके दोनों ने महसूस किया है कि अगर वे डीएमके को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। यही कारण है कि अमित शाह ने खुद चेन्नई में घोषणा की कि भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन राजनीतिक उदासीनता से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। स्पष्ट है कि सबको लग रहा था बीजेपी तमिलनाडु में 2026 का विधानसभा चुनाव अन्ना मलाई के नेतृत्व में लड़ेगी। यह भी चर्चा थी कि अन्ना मलाई आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सभी ने महसूस किया कि राजनीति में ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रोटी पलट दी। अचानक अन्ना मलाई को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। शीर्ष नेतृत्व को यकीन था कि द्रमुक के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जब तक कि उन्हें राज्य अध्यक्ष के पद से हटा नहीं दिया जाता। इसलिए पार्टी ने उनके स्थान पर नयनार नागेंद्र को नियुक्त किया और तुरंत भाजपा-द्रमुक गठबंधन के गठन की घोषणा की। 64 वर्षीय नयनार नागेंद्रन ने 12 अप्रैल को भाजपा के तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। नागेंद्रन एक मृदुभाषी व्यक्तित्व हैं। वे दक्षिण तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह अन्ना मलाई की तरह आक्रामक नहीं हैं। तो पार्टी के एजेंडे को कैसे लागू किया जाएगा? गठबंधन भाजपा एआईएडीएमके नेताओं की बातों को स्वीकार कर गठबंधन चलाना चाहती है। स्टालिन सरकार को हराना ही भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के सामने एकमात्र एजेंडा है। लोकसभा चुनाव के मामले में तमिलनाडु पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा ने कर्नाटक में पैठ बनाई, लेकिन केरल और तमिलनाडु में ज्यादा पैठ नहीं बना सकी, और अब, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने पार्टी विस्तार का एजेंडा तैयार करने के लिए अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन किया है।भाजपा ने तमिलनाडु में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 11 फीसदी वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार सांसद नहीं चुना गया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई भी हार गए थे। भाजपा आलाकमान ने महसूस किया कि पार्टी का तमिलनाडु में कोई बड़ा आधार नहीं है और अपने दम पर चुनाव लड़ना लाभदायक नहीं है। जैसे ही एक पुराने सहयोगी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार पार्टी में जोर पकड़ने लगा, एआईएडीएमके पार्टी, जिसने भाजपा छोड़ दी थी, को फिर से भाजपा द्वारा दरकिनार कर दिया गया। संसद सत्र के अंत में, एआईएडीएमके नेता दिल्ली गए और अमित शाह के साथ बातचीत की और अमितभाई भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन की घोषणा करने के लिए चेन्नई गए।2024 के लोकसभा चुनावों में, डीएमके सांसदों ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके को 46।9 प्रतिशत वोट मिले। यह 1991 के बाद से डीएमके द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर था। 2024 में, भाजपा ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर जगह हार गई। भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनावों में 3.6 प्रतिशत, 2024 में 5.5 प्रतिशत वोट मिले। 2009 में, इसे 2।3 प्रतिशत वोट और 2004 में 5.1 प्रतिशत वोट मिले। द्रमुक के पास अन्नाद्रमुक और भाजपा की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है। स्टालिन के पास पलानीस्वामी की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है, लेकिन उन्हें सत्ता विरोधी लहर से भी पीड़ित होने की संभावना है। तमिलनाडु में, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को महत्व दिया है। डेढ़ साल के अंतराल के बाद, भाजपा और अन्नाद्रमुक ने गठबंधन में फिर से प्रवेश किया है। हाल ही में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) नेतृत्व का मानना रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके का मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास मजबूत कैडर बेस की कमी है।

भाजपा का मानना है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले स्टालिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दे बनाने में एक ताकत के रूप में काम करेगा।संघ के लिए द्रविड़ मतदाता अब द्रविड़ पार्टियों के पक्ष में चुनावी यथास्थिति में विश्वास नहीं करता। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "अब आजीविका, काम के अवसर और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं, और हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ भावनाओं का भड़कना भी बड़ा मुद्दा है। ज्ञात हो कि किसी समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है, एआईएडीएमके की शक्तिशाली नेता थीं। मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। 25 मार्च, 1989 की घटना ने विधानसभा में भारी हंगामा किया था।

हंगामा मच गया। उस दिन राज्य का बजट पेश किया जाना था। हालांकि, जैसे ही विपक्ष की नेता जयललिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवैध कार्रवाई की है, न केवल उनके फोन टैप किए जा रहे थे, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच खींचतान शुरू हो गई। किसी ने जयललिता की साड़ी खींची, किसी ने उसके बाल खींचे। एक ऐसी घटना जिसने संसदीय लोकतंत्र को काला कर दिया। जयललिता ने संकोच नहीं किया। उसने दृढ़ता से कहा झ आज मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। अगली बार जब मैं सदन में कदम रखूंगी, मुख्यमंत्री के रूप में.. जयललिता दो साल बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सदन में दोबारा पहुंची हैं। उसने अपनी बात सच कर दी। 1991 से 2016 तक, वह 14 साल से अधिक यानी 5238 दिनों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं।

संपादकीय

सरकार को चुनौती

अमृता आर. पंडित

भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नैशनल बैंक से तकरीबन साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपयों के गबन का आरोप है। मोदी अभी लंदन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है। इस घोटाले में उसकी पत्नी एमी और भाई निशाल भी मुख्य अभियुक्त हैं। चोकसी मुंबई की अदालत में हलफनामा दे कर भारत आने में अक्षमता जाहिर कर चुका है। वह कैंसर का मरीज है, जिसका इलाज बेल्जियम में चल रहा है। भारतीय एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के साथ मिल कर प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही हैं। बैंक ने 2018 में पहली बार मोदी, चोकसी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। जांच के बाद यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला निकला। इसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत भी पाई गई। हालांकि मोदीकाल में होने वाले बैंक घोटालों में यह अकेला नहीं है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार 2012-16 के दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाइस हजार करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 429, आईसीआईसीआई के करीब 455, स्टैंर्डड बैंक के 244 और एचडीएफसी बैंक के 237 के करीब धोखाधड़ी के मामले पकड़े जाने की पुष्टि हुई है। मोदी के इस घोटाले के बाद पीएनबी ने अपने बीस कर्मचारियों को निलंबित भी किया था। बैंकों के इस गोरखधंधे में बैंककर्मियों की मिली-भगत पकड़ी गई है। इसी दरम्यान देश से भाग चुके आर्थिक अपराधी विजय मल्या पर भी बैंकों को साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। कहने में दोष नहीं है कि प्रत्यर्पण संधि के बावजूद कानूनी प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, और आरोपियों को स्वदेश लाने में सालों लग जाते हैं। चोकसी का मामला भी अभी फेडरल पब्लिक जस्टिस और फॉरेन अफेयर्स की निगरानी में होगा। सरकार किस हद तक दोषी को वापस लाने की कवायद करती है, यह तो वक्त ही बताएगा। धोखाधड़ी के इस धन की वसूली और सजा देने में लगने वाले समय की चर्चा अभी बेमानी है क्योंकि सार्वजनिक बैंकों में इतने बड़े आर्थिक घोटालों में सरकार की भूमिका भी संदिग्ध ही पाई जाती रही है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बातें करने वाले सत्ताधारी दल को इसे चुनौती की तरह देखना चाहिए।

चिंतन-मनन

प्रेम और सहयोग का नाम है परिवार

पारिवारिक सदस्यों के त्याग, सहयोग, स्वच्छता, प्रेम, संतुष्टि व व्यसनमुक्ति से ही परिवार संयुक्त और समृद्धिशाली बनता है। वे सौभाग्यशाली हैं जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तथा जिन्हें माता -पिता का सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। विश्व बंधुत्व की बात करने वालों को पहले अपने परिवार में बंधुत्व बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार टूट रहे हैं। हम अधिकारों की बजाए एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, तभी हमारे परिवार खुशहाल और सुदृढ़ होंगे। एक माता-पिता अपने पाँच-पाँच बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करके योग्य बना देते हैं जबकि पाँच-पाँच बच्चे बुढ़ापे में अपने एक माता-पिता को संभालने से कतराते हैं। आज हम जितने बूढ़े दादा-दादी के प्रति लापरवाह हैं यदि हमारे बचपन में वे हमारे प्रति इतने ही लापरवाह होते तो हमारी क्या दुर्गति हो गई होती। इस बात को युवा पीढ़ी को अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। परिवार में ब्याह कर आई नई बहू को चाहिए कि जितने उम्र का पति उसे मिला है कम से कम उतने साल तो सासससुर का फर्ज मानकर उन्हें निभा देना चाहिए। इस पीढ़ी को व्यसनमुक्त होकर अपने माता-पिता की सेवा करने, उनके प्रणाम करने के तरीको को जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में सदाचार को अपना कर हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचार जीवन का प्रतिबिंब है। संतों की संगति से अच्छे विचार आते हैं। विचार अच्छे होना हमारी जागरूकता को दशार्ता है। हमारे विचार हमारे जीवन का परिचय देते हैं। रुपया-पैसे का लालच छोड़कर हमें जीवन में धार्मिक आराधना करते रहना चाहिए। जिससे हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन सार्थक होगा।

नेता या बहरुपिया

हा आज के लोकतांत्रिक भारत में राजनीति एक साधना नहीं, बल्कि एक स्वांग बन चुकी है। स्वांग, जो कभी धर्म का चोला पहनता है, तो कभी जाति का मुखौटा। कभी किसान का हमदर्द बनकर वोट माँगता है, तो कभी जवान के नाम पर सत्ता का सेहरा बांधता है। पर भीतर का चेहरा-वह असली चेहरा-इतना बदल चुका है कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन सच में जनसेवक है और कौन जनभावनाओं का व्यापारी। राजनीति में विचारधारा कभी ध्रुवतारा हुआ करती थी-जो पार्टी या नेता एक बार जिस पथ पर चला, वही उसका मार्ग रहता। पर आज स्थिति यह है कि नेता सुबह एक पार्टी में होते हैं, और शाम को दूसरी में। सत्ता की भूख, पद की लालसा और स्वार्थ ने विचारधारा को अर्थहीन बना दिया है। आज का नेता जिस विचारधारा को कल तक कोसता था, वही आज उसकी शान बन जाती है। राजनीति में सिद्धांत अब संग्रहालय की वस्तु हो चुके हैं। आज का नेता बहरुपिया है-वह जनता के सामने कुछ और होता है और सत्ता के गलियारों में कुछ और। चुनावों से पहले वह गली-गली घूमता है, हर दरवाजे पर दस्तक देता है, ह्यआपका सेवक हूँह्ल कहता है, और चुनाव जीतने के बाद पांच साल के लिए खुद को जनता से ऊपर समझने लगता है। बहरुपियेपन की यह प्रवृत्ति केवल भाषणों या वादों तक सीमित नहीं है। आज का नेता अपने पहनावे, बोलचाल, मंच पर अभिनय और सोशल मीडिया की स्क्रिप्टेड उपस्थिति तक में एक कुशल कलाकार बन गया है। कभी वह किसान की झोपड़ी में भोजन करता दिखाई देता है, कभी दलित बस्ती में रात्रि विश्राम करता है-पर जैसे ही कैमरा हटता है, वास्तविकता भी बदल जाती है।

सवाल यह है कि जनता कब तक इस अभिनय को सहती रहेगी?

इस बहरुपिया संस्कृति ने राजनीति को मजाक बना दिया है। नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे शब्द अब केवल घोषणापत्रों की शोभा बनकर रह गए हैं। विचारधारा की जगह अब अवसरवादिता ने ले ली है। एक ही नेता आज किसी दल में है, कल किसी और में-जहाँ सत्ता मिले, वहीं उसका धर्म, जाति और निष्ठा भी बदल जाती है।लेकिन दोष केवल नेताओं का नहीं। जिस मीडिया को बहरुपियों का आईना बनना था, वह भी अब उनकी आँख बन गया है-जो वही देखता है, जो वे दिखाना चाहते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता अब चाटुकारिता में बदलती जा रही है। इससे जनता के सामने केवल वो तस्वीरें आती हैं, जो स्वांग को सत्य सिद्ध करती हैं। बहरुपियों के इस खेल में जब जनता ताली बजाना शुरू कर दे, तो वह लोकतंत्र नहीं, तमाशा बन जाता है। सवाल उठाने वाली जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है, लेकिन जब वह भावनाओं में बहकर निर्णय लेना शुरू कर दे, तो मंच पर बहरुपियों की भरमार हो जाती है। जनता भी इस अभिनय को देखकर ताली बजाना सीख गई है। हर बार भावनाओं में बहकर बहरुपिए चुन लिए जाते हैं-जो सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही जनभावनाओं को भुला देते हैं।समय आ गया है कि हम नेता के चेहरे नहीं, चरित्र को पहचानें। मंच पर बोले गए शब्दों को नहीं, कार्यकाल के कार्यों को याद रखें। बहरुपिया राजनीति से मुक्ति तभी संभव है जब जनता सजग, सचेत और सवाल पूछने वाली बने। लोकतंत्र को सजाना है, तो बहरुपियों को बेनकाब करना ही होगा। क्योंकि लोकतंत्र अभिनय का नहीं, उत्तरदायित्व का मंच है।

योगेन्द्र सिंह

धर्म जीवन का हिस्सा या 'आध्यात्मिक उद्योग'

राजेश श्रीवास्तव

क भारत में धर्म हमेशा से सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक नया रूप उभरा है-जिसे कुछ लोग 'आध्यात्मिक उद्योग' कहने लगे हैं। यहां बाबा-गुरु अब केवल उपदेशक नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति और लाखों फॉलोअर्स वाले 'ब्रांड' बन चुके हैं। इन बाबाओं की लोकप्रियता इतनी है कि छोटे शहरों और गांवों में भी उनके प्रवचन के पोस्टर महीनों पहले लग जाते हैं।

दरबार लगते हैं, कथाएं होती हैं, जिनमें भीड़ ही नहीं, बड़े कारोबार और नेताओं की उपस्थिति भी दिखती है। महाराष्ट्र के शिर्डी से लेकर मध्यप्रदेश के छतरपुर तक, पंजाब के डेरा सच्चा सौदा से लेकर तमिलनाडु के ईशा फाउंडेशन तक, भारत के हर हिस्से में कोई न कोई 'गुरुधाम' मौजूद है। इन संस्थाओं के पास हजारों एकड़ जमीन, निजी विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल और मीडिया चैनल तक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बाबा रामपाल से जुड़े एक मामले में टिप्पणी की थी कि धार्मिक आस्था के नाम पर कानून को हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता।ह्व इसी तरह डेरा सच्चा सौदा से जुड़े एक केस में अदालत ने कहा था, धर्मगुरु यदि आपराधिक कृत्य करें, तो उन्हें अलग छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन यथार्थ यह है कि कई बाबा आज भी राजनेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। चाहे मामला चुनावों का हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, ये चेहरे अक्सर मंच के बीचोबीच होते हैं। 2019 के आम चुनावों में कुछ बाबाओं ने सार्वजनिक रूप से एक खास पार्टी को समर्थन देने की घोषणा भी की थी। हरियाणा में एक पत्रकार की हत्या के मामले में एक बाबा का नाम आया था, जबकि राजस्थान में बलात्कार के दोषी एक बाबा के समर्थन में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी थी। यह बताता है कि उनके अनुयायियों की आस्था कानून और संविधान से भी ऊपर जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बाबाओं की संस्थाओं को करोड़ों की सरकारी जमीन बेहद कम कीमत पर दी गई। तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन पर आरोप है कि उन्होंने वन भूमि पर निर्माण किया, जिस पर एनजीटी ने सवाल उठाए थे। वहीं मध्यप्रदेश में बागेश्वर धाम को लेकर जमीन अधिग्रहण और सरकारी समर्थन की खबरें आईं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात बदतर

है, लेकिन बाबा लोगों को यह यकीन दिला देते हैं कि सबकुछ आस्था से संभव है। जो व्यवस्था को जवाबदेह बनाना चाहिए था, वह अब 'चमत्कार' में विश्वास करने लगा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि धर्मगुरुओं की अपील वहाँ साबासो अधिक चलती है जहाँ आलोचनात्मक सोच की कमी हो। यह कमी स्कूलों में तर्कशील पाठ्यक्रमों की अनुपस्थिति और परिवारों में अंधश्रद्धा के माहौल से आती है। महिलाएं इस प्रभाव का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से कई घरेलू हिंसा, सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक निर्भरता का सामना करती हैं। ऐसे में 'कोई चमत्कारी समाधान' उन्हें आकर्षित करता है। इसी वजह से कई बाबाओं पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं - और फिर भी वे अपने प्रभाव को बनाए रखते हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की थी, अंधश्रद्धा के नाम पर अपराध को छिपाना लोकतंत्र और कानून दोनों का अपमान है। यह टिप्पणी सीधा संकेत देती है कि राज्य को इन विषयों पर अधिक सक्रिय और पारदर्शी होना होगा। लेकिन आलोचकों की संख्या सीमित है। जो लोग इन बाबाओं पर सवाल उठाते हैं, उन्हें 'धर्म विरोधी' करार देकर चुप कराने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया पर इनके समर्थक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि संगठित ट्रोलिंग एक आम बात है। प्रशासन भी अकसर इन पर सख्ती बरतने से बचता है। 2013 में जब हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो कई अफसरों के तबादले हुए थे। यही वह राजनीतिक दबाव है, जिससे कानून कई बार पीछे हट जाता है। इन स्थितियों को देखते हुए सवाल यह है कि क्या भारत में आध्यात्मिकता अब एक राजनीतिक-आर्थिक ताकत बन चुकी है? क्या संविधान का धर्म निरपेक्ष चरित्र इन ताकतों के सामने असहाय होता जा रहा है? भारत के लोकतंत्र में धर्म का स्थान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जब धर्म ही सत्ता का उपकरण बन जाए, तो समाज को सोचना होगा कि आस्था की आड़ में कौन-सी व्यवस्था पोषित हो रही है और कौन-सी मयार्दाएं टूट रही हैं

संक्षिप्त डायरी

बिजली पर सबसिडी देकर भाजपा सरकार ने एक और संकल्प किया पूरा: बिधूड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण दिल्ली में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में बिजली की सबसिडी जारी रखने का फैसला करके दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोल रहे थे और उस झूठ का पदार्फाश हो गया है। बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों के दौरान जो संकल्प पत्र पेश किया था, उसके सभी संकल्पों को एक-एक करके पूरा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना लागू करने और महिलाओं की पेंशन की व्यवस्था करने के बाद अब भाजपा ने दिल्ली की जनता को बिजली की सबसिडी देने का अपना वादा भी पूरा कर दिया है। भाजपा का प्रत्येक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इसलिए हर संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनके साथी चुनावों के दौरान यह कुप्रचार करते रहे कि अगर भाजपा साा में आ गई तो बिजली पर सबसिडी खत्म कर दी जाएग या मु त पानी बंद हो जाएगा या महिलाओं की मु त यात्रा बंद की जाएगी। हमने उसी समय यह वचन दिया था कि सभी सुविधाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। भाजपा अपना प्रत्येक वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सबसिडी जारी रखने का फैसला करके केजरीवाल एंड पार्टी के झूठ का एक बार फिर जनता के सामने पदार्फाश कर दिया है।

खराब श्रेणी में पहुंची राजधानी दिल्ली की हवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर बढड़े लगा है। बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवाा सूचकांक 200 के पार यानी खराब श्रेणी में रहा। हालांकि, हवा की र तार बढड़े के चलते अगले दो दिनों के बीच ए यूआई में सुधार की संभावना है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवाा सूचकांक 220 अंक पर रहा। एक दिन पहले यह 180 अंक पर था। यानी चौबीस घंटे में सूचकांक में 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई। वहीं, तीन इलाकों का सूचकांक बुधवार को 300 पार यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा।

जेएनयूएसयू चुनाव में अध्यक्ष पद पर 48 दावेदार

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन हुआ। सबसे अधिक अध्यक्ष पद पर 48 छात्रों ने नामांकन किया। उपाध्यक्ष पद पर 41, जनरल सेक्रेटरी पद पर 42 और सह सचिव के पद पर 34 छात्रों ने नामांकन किया। जेएनयू के मु य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ा में बताया गया है सभी चार पदों पर 250 उमीदरों ने दावेदारी प्रस्तुत की। हालांकि बुधवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। मंगलवार को दिन भर कैंपस में छात्रों ने अपने अपने संगठनों के लिए कैंपेनिंग की। बहुत संभावना है कि इस बार भी वाम संगठन छात्र संघ चुनाव में मिलकर लड़े। जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एबीवीपी की ओर से इस बार थीटे शांभवी प्रमोद,अनुज दमाड़ा, कुणाल राय, विकाश पटेल, राजेश्वर कांत दुबे, शिखा स्वराज, निट्टू गौतम, अरुण श्रीवास्तव तथा आकाश कुमार रवानी मैदान में हैं। इन सभी संभावित प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन्हीं नामों में से जेएनयूएसयू सेन्ट्रल पैनल के लिए चार नाम तय होंगे। एबीवीपी के कार्यकर्ता अलग-अलग समूहों में हॉस्टल टू हॉस्टल, लास टू लास कैंपेन के माध्यम से प्रत्येक छात्र- छात्राओं तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से कैंपस में वामपंथी छात्र संगठन भी कैंपस के मुद्दों के साथ छात्रों से मिल रहे हैं। ज्ञात हो कि जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव के साथ-साथ 42 काउंसलर पदों के लिए भी चुनाव होने हैं, जो विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और एक विशेष कंबाइंड सेंटर में संपन्न होंगे। जेएनयूएसयू का मतदान 25 अप्रैल को होगा।

मिरांडा हाउस में सजी टे पेस्ट 2025 की रंगारंग महफिल: संस्कृति, रचनात्मकता और सततता का अद्भुत संगम

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज मिरांडा हाउस में 15 और 16 अप्रैल को वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव टे पेस्ट 2025 का भव्य आयोजन हुआ। 'स्पे ट्रम ऑफ सिफनी यानी 'रागों का इंद्रधनुष थीम के तहत यह दो दिवसीय उत्सव कला, संस्कृति और रचनात्मकता की अद्वितीय झलक लेकर आया, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई दिया। साथ ही, इस वर्ष महोत्सव ने सतत विकास और पर्यावरण जागरूकता को भी प्रमुखता से सामने रखा। कार्यक्रम की शुरूआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर बिजयालक्ष्मी नंदा ने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक चेतना और आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। पउन्होंने कहा कि यह केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहाँ युवा छात्राएं अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देती हैं, सहयोग की भावना को अपनाती हैं और हमारे समय की सबसे जरूरी सामाजिक व सांस्कृतिक बातों पर विचार करती हैं। उद्घाटन प्रस्तुति उार पूर्व की संस्था द्वारा दी गई, जो कॉलेज की क्षेत्रीय विविधता को समर्पित थी। इसके बाद मृदंग-मिरांडा हाउस की भारतीय नृत्य संस्था-द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय और समकालीन नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव की प्रमुख प्रस्तुतियों में से एक रहा तंज: रॉयल रंबल '25, जिसमें विभिन्न कॉलेजों की टीमों ने मंच पर अपनी नृत्य प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। तत्वा नामक लाइव यूजन बैंड ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज परिसर के विभिन्न स्थानों पर एक साथ कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अद्वितीया आर्ट एग्ज़िबिशन ने छात्राओं और शिक्षकों की कलात्मक रचनाओं को प्रस्तुत किया।

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बीईएसएस का दौरा किया, कहा- बैटरी बैंक को जल्द किया जाएगा जनता को समर्पित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को किलोकरी स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने बीएसईएस अधिकारियों के साथ पावर ग्रिड का निरीक्षण किया।

आशीष सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ÷बहुत जल्द यह बैटरी बैंक औपचारिक रूप से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यह एक नई तकनीक है, जिसमें ग्रिड से बिजली बैटरी बैंक में संग्रहित होगी और बाद में, एक बड़े औद्योगिक इन्वर्टर के माध्यम से, ग्रिड या बुनियादी ढांचे के फेल होने पर इसका उपयोग किया जाएगा। हमारी सरकार बिजली ढांचे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा के साथ विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए इस तरह के पावर बैंक बनाए जा रहे हैं। यह हमारा पहला प्रयोग है, जिसकी शुरुआत जल्द होगी।'

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली के बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। हमारी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नई तकनीकों, प्रभावी ढांचे और विश्वस्तरीय सुरक्षा मानकों के साथ विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम केवल 50-60 दिन पुरानी सरकार हैं, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार, आधुनिकीकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय से ही भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाजपा सरकार आएगी तो बिजली सब्सिडी बंद कर देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी को जारी रखने का फैसला लिया है, यह जारी रहेगी। जो लोग बिजली संकट की झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, उन्हें यह आधुनिक ढांचा और तथ्य दिखाएं। बता दें कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि कैबिनेट ने चार प्रमुख वर्गों के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। इसमें किसानों, 1984 सिख दंगा पीड़ितों, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं और वकीलों के चेंबर से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी शामिल है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की ओर से सब्सिडी खत्म होने की अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद हैं, और यह फैसला उन सभी दावों का जवाब है।

जयशंकर का विदेशी राजदूतों से पूर्वोत्तर को जानने, इसकी खूबियों को अपनी सरकारों से साझा करने का आग्रह

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ेगी, साथ ही उन्होंने विदेशी राजदूतों से उस क्षेत्र को देखने ,समझने और अपनी सरकारों तथा उद्योग जगत के साथ क्षेत्र की खासियत को साझा करने का आग्रह किया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा आयोजित होने जा रहे 'पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025' के लिए राजदूतों की एक बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कई प्रमुख भारतीय नीतियों - 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' या 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (बिम्सटेक) के केंद्र में है।

उन्होंने कहा, ''पूर्वोत्तर हमारे पांच पड़ोसियों से जमीन से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप और 'आसियान' (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) देशों से जुड़ी हैं।''

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के निकटतम पड़ोसियों से जुड़ी कई हालिया पहल इसी क्षेत्र से निकली हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना जैसी अन्य पहल भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, ''हर मायने में यह एक केंद्र है, जिसकी प्रासंगिकता समय के साथ और बढ़ेगी।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ''हम चाहते हैं कि आप इसकी कई खूबियों से परिचित हों और इसे अपनी सरकार और उद्योग जगत के साथ साझा करें। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें।''

बाद में मंत्री ने राजदूतों के साथ बैठक के बारे में 'एक्स' पर पोस्ट किया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार, पर्यटन केंद्र और वैश्विक कार्यस्थल में योगदानकर्ता के रूप में पूर्वोत्तर की बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

उपराज्यपाल के खिलाफ मेधा पाटकर के मानहानि मामले की तारीख 20 मई के बाद तय करें: उच्च न्यायालय

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत से बुधवार को कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा वर्ष 2000 में राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई की तारीख 20 मई के बाद तय करे।

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की नेता ने सक्सेना के खिलाफ उस वक्त मामला दाखिल किया था, जब सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ के प्रमुख थे और उन्होंने (सक्सेना ने) कथित तौर पर एक अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित कराया था।

न्यायमूर्ति शालिन्दर कौर ने अधीनस्थ अदालत से कहा कि अंतिम बहस के लिए निर्धारित मानहानि मामले को 20 मई के बाद सूचीबद्ध किया जाए। उच्च न्यायालय 20 मई को ही पाटकर की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने मामले में एक नए गवाह से जिरह करने की मांग की है।

न्यायाधीश ने कहा, ''अधीनस्थ अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अदालत द्वारा दी गई तारीख के बाद ही सुनवाई की तारीख दे।' उच्च न्यायालय ने यह निर्देश पाटकर की उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने मानहानि मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

यह अर्जी पाटकर की उस लंबित याचिका में दायर की गयी है, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ अदालत के 18 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। इसमें मामले में नए गवाह से जिरह करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को बताया गया कि अधीनस्थ अदालत ने 28 मार्च को इस मामले में अंतिम बहस के लिए 19 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी। उच्च न्यायालय से अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए वकील ने कहा कि यदि कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका निरर्थक हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने 27 मार्च को अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ पाटकर की याचिका पर सक्सेना को नोटिस जारी किया था।

सक्सेना के वकील ने कहा कि याचिका पर जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और उन्होंने 24 साल पुराने मामले में अंतिम दलीलें सुनने के लिए अधीनस्थ अदालत से अनुरोध किया। अधीनस्थ अदालत ने 18 मार्च को पाटकर की एक नए और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को 'ऐसी युक्तियों से बंधक नहीं बनाया जा सकता।' इसने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित था और शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करते समय शुरू में सूचीबद्ध सभी गवाहों से पहले ही जिरह कर ली है।

अधीनस्थ अदालत ने कहा कि यदि पक्षकारों को बाद के चरण में? मनमाने ढंग से नए गवाह पेश करने की अनुमति दी गई तो मुकदमे कभी समाप्त नहीं होंगे। पाटकर ने 17 फरवरी को अधीनस्थ अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर अतिरिक्त गवाह नंदिता नारायण से जिरह की मांग की थी और कहा था कि यह 'मौजूदा मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक हैं।'

सक्सेना के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका न्यायिक कार्यवाही में देरी करने के लिए 24 साल के अंतराल के बाद दायर की गई है। पाटकर और सक्सेना के बीच वर्ष 2000 से कानूनी लड़ाई चल रही है, जब पाटकर ने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ कथित तौर पर विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सक्सेना के खिलाफ मामला दायर किया था।

उस समय अहमदाबाद स्थित गैर सरकारी संगठन 'काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज' के प्रमुख रहे सक्सेना ने अपने खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक बयान प्रेस को जारी करने के लिए 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मामले दायर किए थे।

सक्सेना द्वारा दायर एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पाटकर को एक जुलाई 2024 को पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

नरेला से बांग्लादेशी दंपति को उनके नाबालिग बच्चे के साथ पकड़ा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शहर के बाहरी उत्तरी हिस्से के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी दंपति और उसके बच्चे को पकड़ा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी) निधिन वलसन ने एक बयान में कहा, ''सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें निर्वासन केंद्र भेज दिया जाएगा।'' उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उस क्षेत्र में एक किराये के कमरे तक पहुंची जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि दोनों वयस्कों की पहचान 36 वर्षीय हिलाल हुसैन और उसकी 32 वर्षीय पत्नी तस्लीमा अख्तर के रूप में हुई है। अधिकारी के मुताबिक हिलाल मूल रूप से बांग्लादेश के बरगुना जिले का निवासी है और कई सालों से भारत में रह रहा था। उन्होंने बताया कि वह शुरू में अपने माता-पिता के साथ यमुना पुश्ता झुग्गी में रहता था और बाद में बवाना में जेजे कॉलोनी में रहने लगा। वह एक स्थानीय दूध की दुकान पर दिहाड़ी कर्मी के तौर पर काम करता है। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान हिलाल ने खुलासा किया कि उसने करीब पांच साल पहले बांग्लादेशी नागरिक तस्लीमा से शादी की थी। तब से यह दंपति नरेला में रह रहा था। पुलिस ने पाया कि आधार कार्ड होने के बावजूद हिलाल भारत में कानूनी प्रवास की पुष्टि करने वाले कोई भी वैध यात्रा या आव्रजन दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।

राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है उन्हें देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है, कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकते: मनजिंदर सिंह सिरसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो बयान में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने और भ्रष्टाचार करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हें लगता है कि इसका उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता। नेशनल हेराल्ड अखबार को देश की जनता ने एक-एक दो-दो रुपये इकट्ठा करके देश की आजादी की लड़ाई के लिए शुरू किया था, उसकी सारी संपत्ति को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एजीएल के माध्यम से अपने नाम करवा लिया।'

उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों को सीज कर रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहा है, तो वे सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे देश के कानून पर विश्वास नहीं है। मैं देश के कानून को नहीं मानता।

उन्होंने आगे कहा कि देश का कानून राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी लागू होता है। यदि आपको कोई गलतफहमी है तो उसे ठीक कर लीजिए। शायद 60 साल में लागू नहीं हुआ होगा, क्योंकि गांधी परिवार और नेहरू परिवार की चल रही थी। देश का कानून मजबूत है और गांधी परिवार को सबक सिखाने के लिए यही उचित कानून है, आपको इसका पालन करना होगा। इस कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है। नेशनल हेराल्ड घोटाला गांधी परिवार के लालच को बेनकाब करता है। 2008 में अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस ने पार्टी फंड से 90 करोड़ एक निजी कंपनी एजेएल को दे दिए, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। जब गांधी परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं देश के कानून को नहीं मानता, राहुल गांधी, सड़कों पर गुंडागर्दी करने से आप कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते, आपने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा।'

पंजाब के व्यक्ति को फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भेजने की कोशिश करने के आरोप में तीन एजेंट गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर पंजाब निवासी एक व्यक्ति को कनाडा भेजने का प्रयास करने के आरोप में तीन ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल को कमलजीत सिंह के नाम का भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से टोरंटो के लिए उड़ान भरने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि आव्रजन जांच के दौरान अधिकारियों को तब शक हुआ, जब पासपोर्ट पर लगी तस्वीर व्यक्ति की शक्ल से मेल नहीं खा रही थी। बयान के मुताबिक, पूछताछ करने पर यात्री ने अपनी असली पहचान पंजाब के मोहाली निवासी मनप्रीत सिंह (40) के रूप में बताई। बयान के अनुसार, मनप्रीत ने स्वीकार किया कि उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कनाडा की यात्रा करने के लिए एक एजेंट रूपेंद्र सिंह (29) को 20 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। उसने बताया कि पूरा सौदा 32 लाख रुपये में तय हुआ था। बयान में कहा गया है कि मनप्रीत अपने एक दोस्त के जरिये रूपेंद्र से मिला था और बाद में उसकी रूपेंद्र के साथियों-गुजरात के हरीश चौधरी (24) और उत्तर प्रदेश के विशाल धीमान (27) से दिल्ली के महिपालपुर के एक होटल में मुलाकात हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि होटल में मनप्रीत को फर्जी पासपोर्ट सौंप दिया गया और बाद में आरोपी उसे हवाई अड्डे तक ले गए। उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के बाद रूपेंद्र, हरीश और विशाल को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने कहा, ''हमने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उनके वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं। हम इसी तरह की आव्रजन धोखाधड़ी के अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता का पता लगा रहे हैं।''

एमसीडी में 25 अप्रैल को महापौर और उपमहापौर के होंगे चुनाव, भाजपा का पलड़ा दिख रहा है भारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब दूसरे रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में महापौर और उपमहापौर पदों के लिए चुनाव 25 अप्रैल को होंगे। हर वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होता है, जो आमतौर पर अप्रैल में आयोजित की जाती है। चुनाव होने तक मौजूदा महापौर पद पर बने रहते हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी (आप) के महेश खींची इस पद पर काबिज हैं और चुनाव तक वही कार्यरत रहेंगे। 11 अप्रैल को जारी आदेश में एमसीडी सचिव शिव प्रसाद ने कहा, 'एमसीडी की अप्रैल की सामान्य बैठक 25 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2 बजे अरुणा आसफ अली सभागार, सिविक सेंटर में आयोजित की जाएगी, जिसमें महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी कराया जाएगा।' दिल्ली में निगम चुनाव हर पांच साल में होते हैं जबकि महापौर का चुनाव हर साल होता है। पिछला महापौर चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, क्योंकि अप्रैल 2024 में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण समय पर मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इस साल महापौर पद सभी पार्षदों के लिए खुला है, क्योंकि पहले कार्यकाल में महिलाओं और तीसरे कार्यकाल में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू होता है। इस बार कोई आरक्षण लागू नहीं है। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) के कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिससे भाजपा को आगामी महापौर चुनाव में बढ़त मिल गई है। महापौर चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में 250 पार्षद, सात लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 14 विधायक शामिल होते हैं। 10 नामित पार्षद (एल्डरमेन) भी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 22 मार्च को एमसीडी के लिए 14 विधायकों को नामित किया, जिनमें 11 भाजपा और तीन आप के विधायक हैं। 2022 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर भाजपा (104 सीटें) को हराया था। 14 नवंबर, 2024 को हुए महापौर चुनाव में 'आप' उम्मीदवार को केवल तीन वोटों के अंतर से जीत मिली थी, जिसमें क्रॉस वोटिंग की भूमिका रही।

दिल्ली की द्वारका अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के द्वारका स्थित अदालत परिसर में बुधवार को बम की धमकी मिलने के बाद अदालत को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न करीब पौने 11 बजे पीसीआर को कॉल मिली जिसमें बताया गया कि द्वारका अदालत को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। उन्होंने बताया कि ईमेल मंगलवार रात करीब नौ बजे मिला था और अदालत के अधिकारियों ने बुधवार सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देखी 'केसरी चैप्टर 2'

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यहां एक विशेष कार्यक्रम के तहत अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' देखी और भारतीय इतिहास के एक अनदेखे अध्याय को उजागर करने वाली इस फिल्म की प्रशंसा की।

'केसरी चैप्टर 2', जलियांवाला बाग नरसंहार की एक अनकही कहानी को बयां करती है और यह फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ-साथ अक्षय और उनके सह-कलाकार आर माधवन के संग फिल्म देखी।

पुरी ने फिल्म देखने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, 'मैं चाहता हूं कि युवा इस फिल्म को देखें, इससे प्रेरणा लें और दिखाएं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ऐसे लोग खड़े होते हैं और धारा के विपरीत काम करते हैं। और इसी तरह देश स्वतंत्र हुआ। इसी तरह हम आज जो हैं, वह हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहे हैं, इसी तरह हम आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं।'

उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने बच्चों के साथ यह फिल्म देखनी चाहिए। पुरी ने कहा, 'मैं इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। इनमें से कुछ चीजों के प्रति कांग्रेस का रवैया, वे अपने परिवार को बढ़ावा देने में इतने व्यस्त रहे हैं कि वे व्यापक वास्तविकता और देश के विकास के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है उसे भूल गए हैं।'

निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित यह फिल्म वकील सी शंकरन नायर की सच्ची कहानी को बयां करती है, जिन्होंने 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

यह फिल्म नायर के प्रपौत्र रघु पलात और उनकी पत्नी पुष्पा पलात की किताब 'द केस दैट शूक द एम्पायर' पर आधारित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि इसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए।

उन्होंने कहा, 'यह एक शानदार फिल्म है। मैंने आधी फिल्म देखी है और पूरी फिल्म देखना चाहूंगी। मैं हमेशा कहती हूं कि हमें अपने देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने देश के लिए जीना शुरू कर सकते हैं।'

रेखा गुप्ता ने कहा, 'देश की आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए जीना शुरू करें।

पर्यावरण बचाने के लिए स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट बनेंगे अभियान का हिस्सा

सीएम योगी के आह्वान पर छात्र बनेंगे पर्यावरण रक्षा के दूत

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर अब स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के छात्र-छात्राएं पर्यावरण बचाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएंगे।

इसके तहत नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, रैली, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मिशन को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा निदेशक पर्यावरण को एक पत्र भेजा गया है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के हर कोने में पर्यावरण जागरूकता की अलख जगाई जाएगी। इस अभियान की सबसे रोचक बात होगी कलात्मक जागरूकता। सड़क किनारे नुक्कड़ नाटकों में दिखाया जाएगा कि प्लास्टिक का कचरा कैसे नदियों को मार रहा है। कठपुतलियों के माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मोटिवेट किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय मेलों में इको-फ्रेंडली प्रदर्शनियां लगेंगी।स्कूली बच्चों को इस मुहिम का यंग फेस बनाया जाएगा। उनके लिए पोस्टर प्रतियोगिता में प्र-कृति को लेकर विभिन्न विषय होंगे।

भाषण प्रतियोगिताओं में बच्चे बताएंगे कि घर में प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम किया जाए। क्विज में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जीतने वाले बच्चों को इको-फ्रेंडली गिफ्ट दिए जाएंगे। पर्यावरण का संदेश लोगों तक पहुंचने के लिए हर बेहतर माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा कि कैसे प्लास्टिक मुक्ति से किसी नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश वायरल किया जाएगा। इसके साथ ही होर्डिंग्स पर तमाम संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यावरण को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदूषण के खिलाफ युद्धस्तर की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण के कारण बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे।

हेरल्ड मामले की जांच और वाड्रा से पूछताछ के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर एक बड़ा बयान

ईडी को समाप्त कर देना चाहिए : अखिलेश

नई दिल्ली / भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन दिनों चचाओं में बना हुआ है. और चचाओं में बने रहने की सबसे बड़ी वजह है नेशनल हेरल्ड और हरियाणा लैंड स्कैम मामले की जांच. ईडी ने जहां नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है, वहीं हरियाणा लैंड स्कैम मामले में ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है. हेरल्ड मामले की जांच और वाड्रा से पूछताछ के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी को कांग्रेस ने ही बनाया था. आज यही ईडी सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस को ही कर रही है. ऐसे में मेरा तो मानना है कि ईडी को ही खत्म कर देना चाहिए. आपको बता दें कि हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है. मंगलवार को उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी. आज एक बार फिर से वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे चुके हैं. ईडी की पूछताछ में शामिल होने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं. ऐसे हमलों से हम और मजबूत होते हैं. साथ ही वाड्रा ने कहा कि जो आज मैं झेल रहा हूं ये उनको भी झेलना होगा. मैं ईडी के हर सवाल का जवाब दूंगा. हम वो लोग हैं जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं. ये तो सिर्फ समय की बात है, ये जरूर बदलेगा. उधर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.यह पहला मामला है, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की राजनीति बताया है.

योगी सरकार की पहल: खगोल विज्ञान में उड़ान भरेंगी केजीबीवी की बेटियां, हर विद्यालय में बनेगी एस्ट्रोनॉमी लैब

एस्ट्रोनॉमी लैब्स से छात्राओं को मिलेगा अंतरिक्ष विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। इसी क्रम में राज्य के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति विद्यालय 4 लाख का बजट निर्धारित किया गया है और कुल 29.84 करोड़ की परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नारी शक्ति' और 'विकसित भारत' के विजन से प्रेरित है, जिसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गति दे रही है। एस्ट्रोनॉमी लैब्स के माध्यम से छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलविज्ञान की वास्तविक जानकारी दी जाएगी, जिससे वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध होकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगी। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और उसमें 54 महिला वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी ने इस पहल को नई ऊर्जा दी है। प्रदेश सरकार चाहती है कि यूपी की बेटियां भी आने वाले समय में इसरो, डीआरडीओ और नासा जैसे संस्थानों में अपनी भूमिका निभाएं। लैब्स में प्लेनेटेरियम की तर्ज. पर छात्राएं सौरमंडल, ग्रह-उपग्रह, खगोलीय घटनाएं जैसे सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण का अध्ययन करेंगी। स्पेस-

क्राफ्ट, मिसाइलें, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस-रो परियोजनाएं और भारतीय वैज्ञानिकों के मॉडल इन प्रयोगशालाओं का हिस्सा होंगे। इस लैब में बालिकाओं द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विभिन्न वर्किंग मॉडल तैयार किए जाएंगे। इन वर्किंग मॉडल का उपयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में किया जाएगा। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के केजीबीवी को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया गया है। फिलहाल 476 उच्चीकृत विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संचालित की जा रही है। इन विद्यालयों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें एक श्रेणी में एकेडमिक ब्लॉक के साथ हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। इस एकेडमिक ब्लॉक में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में केवल विज्ञान वर्ग की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें कक्षा 9 से 12 तक की सभी छात्राओं को फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिन्दी और अंग्रेजी विषय पढ़ाये जाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे विद्यालय उन्हीं क्षेत्रों में विकसित किए जाएं, जहाँ 3 किमी की परिधि में कोई अन्य राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय न हो। इसके साथ ही केजीबीवी परिसर से सटी भूमि की उपलब्धता भी हो।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शिक्षा को नए आयाम मिल रहे हैं।

छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि और समझ विक-सित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बेटियों के लिए उज्ज्वल भविष्य के द्वार खोलने वाली यह योजना 29.84 करोड़ की लागत से लागू की जा रही है, जिसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम अवश्य सामने आएंगे।

उत्तराखंड में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी रेल टनल, जिसकी खोदाई में रेलवे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी ने संयुक्त रूप से सुरंग स्थल का निरीक्षण किया

नई दिल्ली / भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनासू (पौड़ी गढ़वाल) में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत सुरंग संख्या ळ-8 और ळ-8ट के ब्रेकथ्रू के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से सुरंग स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से सुरंग की जानकारी ली। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सुरंग के सफल ब्रेकथ्रू पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उत्तराखण्ड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्द ही इस रेल लाइन पर संचालन शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह (देवप्रयाग सौड़ से जनासु तक) 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग उत्त-राखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लंबी सुरंग है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर सात घंटे से घटकर सिर्फ दो घंटे का हो जाएगा। यह हर मौसम में दूरदराज के इलाकों तक पहुंच आसान करेगा और उत्तराखण्ड में पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह चार धाम रेल परियोजना को पूरा करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इस उपलब्धि के साथ आरवीएनएल ने भारत के सबसे मुश्किल इलाकों में आधुनिक निर्माण तकनीक में अपनी मजबूत जगह बनाई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सुरंग उत्तराखण्ड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएगी। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई गति देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा और गति मिली है। देवप्रयाग-सोड़ से श्रीनगर जनासु तक की यह सुरंग तकनीकी दृष्टि से भी एक बड़ी उपलब्धि है और यह दिखाती है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हम विकास के कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे भी

हो चुका है जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ.धन सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित, आरवीएनएल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गौर, अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक राम चंद्र शेट, जीएम उत्तर रेलवे अशोक कुमार वर्मा, प्रबंधक निदेशक भानु प्रकाश, मुख्य परियोजना प्रबंधक आरवीएनएल अजित यादव, जीएम आरवीएनएल सुमित जैन सहित अन्य उपस्थित थे।

वरिष्ठ पत्रकार पवन राज सिंह के पिता स्वर्गीय तेजपाल सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता और प्रशासनिक लोगों ने श्रद्धांजलि दी

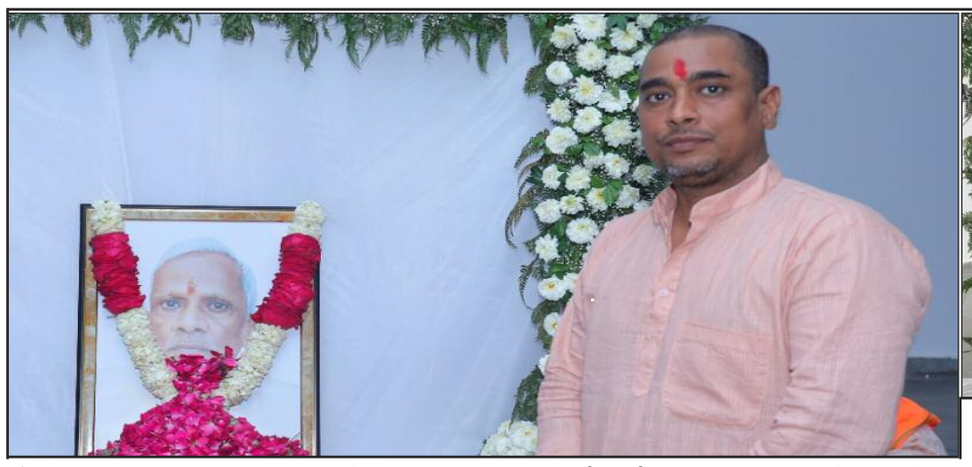

नोएडा/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । वरिष्ठ पत्रकार एवं पीएनआई न्यूज के संपादक पवन राज सिंह के पिता स्वर्गीय तेजपाल सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सेक्टर 56 स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, इनके पिता विद्युत विभाग में सेवारत थे, अपने कार्य के साथ साथ वह सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी समय देते थे, वे अपने पीछे तीन सुपुत्र पवन राज सिंह, राजेंद्र कुमार, ललित कुमार सहित भरापूरा परिवार छोड़ गए है। श्रद्धांजलि सभा में नोएडा विधायक पंकज सिंह, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल, कृष्ण अग्रवाल, राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, पूर्व मंत्री नवाब सिंह नगर, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, पीयूष द्विवेदी, एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन, सुधीर श्रीवास्तव, राकेश कोहली, परविंदर सिंह, संदीप अग्रवाल, आईआईए अध्यक्ष नवीन गुप्ता, निर्मल कांत गोयल, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन से सीपी शर्मा, मोहन कपूर, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल से विकास जैन, लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्टी जगमोहन सेठ, हरीश सभरवाल, इंद्रपाल खंडपुर, पंजाबी विकास मंच से दीपक बिग, संजीव पुरी, पंजाबी एकता समिति से वीरेंद्र मेहता, नरेंद्र चोपड़ा, गौरव चाचरा, लघु उद्योग भारती से सतबीर सिंह, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से सुधीर चंद्र पोरवाल, अमित अग्रवाल, अमित पोरवाल, नवीन पोरवाल, विश्व हिंदू परिषद से राजीव शर्मा, उमानंदन कौशिक, जागृति लीला फाउंडेशन से कुम्मु भटनागर, एमएसएमई इंडस्ट्री एसोसिएशन से सचिन राणा, ब्राह्मण समाज महासंघ से गिरीश मिश्रा, ब्राह्मण समाज सेवा समिति से हरीश मिश्रा, अंतर्यामी सत्संग भवन से प्रवीण बीनू शर्मा, शैल माथुर, श्री नारायण संस्कृतिक चेतना न्यास से राजन श्रीवास्तव, भारतीय सिंधु सभा से नरेश कुमार जोतवानी, पूर्व आईएएस गणेश शंकर त्रिपाठी, ह्म्स लाइफ हॉलिस्टिक से लवलीत पीर, श्री सिद्ध पीठ शनी मंदिर से ठ-ाकुर मानसिंह चौहान, राजीव मिश्रा, नवरत्न फाउंडेशन से अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव व नवरत्न श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद से डॉ एसपी जैन, टीएन गोविल, अतुल कांत वर्मा, प्रताप मेहता, विष्णु गोयल, सत्यनारायण गोयल, फोनरवा से केके जैन, श्री राम मित्र मंडल से धर्मपाल गोयल, मुकेश अग्रवाल, अनिल गोयल, पेइंग गेस्ट हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से विशेष त्यागी, अभिषेक सिंघल, स्याद्वाद युवा क्लब से मनोज जैन, सुनील जैन, कैलाश हॉस्पिटल के वरिष्ठ प्रबंधक विश्व बंधु जोशी, श्री रामा कृष्णा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट से प्रवीण पांडे, राजपुताना विकास महासभा से सत्यपाल सिंह, डॉ सुभाष गुप्ता, मनीष गुप्ता, महेश अवाना, डिंपल आनंद, धर्मेंद्र चौहान, सचिन अंबावत, मुख्तार प्रजापति, जयप्रकाश प्रजापति, गिव्स इंडिया से दिनेश गिरी, गणेश शर्मा, राकेश गर्ग, गंगेश्वर दत्त के साथ-साथ नोएडा के समस्त गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

संक्षिप्त डायरी

"कमाल करदे ओ" म्यूजिक वीडियो उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने रिलीज किया

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी नई फिल्म पॉलिसी और देवभूमि की खूबसूरत वादियों ने फिल्म निमार्ताओं के लिए मुनाफे और लोकेशंस के नए द्वार खोल दिए हैं। यही वजह है कि देश की मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कम्पनी साउंड स्टार्स यूके और स्मृति सहगल ने उत्तराखण्ड का रुख किया है। अपने बैनर के तले उन्होंने 100 म्यूजिक वीडियो बनाने का ऐलान किया है। इसी क्रम में साउंड स्टार्स यूके के "कमाल करदे ओ" म्यूजिक वीडियो आज उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने रिलीज किया है। साउंड स्टार्स यूके के गीत "कमाल करदे ओ" की शूटिंग देहरादून और मसूरी की खूबसूरत लोकेशन पर की गई है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को शामिल करते हुए उत्तराखण्ड सरकार और फिल्म विकास परिषद के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है। साउंड स्टार्स यूके की निमार्ता स्मृति सहगल ने बताया कि हम उत्तराखण्ड की सभी अनदेखी लोकेशन पर अपने ज्यादातर गीतों की शूटिंग करेंगे। इन गीतों में स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फिल्म डेस्टिनेशन के विजन पर फिल्म और म्यूजिक एल्बम का निर्माण होगा।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पीएम-एबीएचआईएम और पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत शीघ्र ही ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (डीआईपीएचएल) एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक को तैयार कर शीघ्र संचालन शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी यूनिटों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन किए जाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध संचालन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक रूप से इन यूनिटों की निगरानी की जाए। साथ ही जिन यूनिटों का कार्य पूर्ण हो चुका है उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक पंजीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा के जिला कार्यान्वयन समिति एवं यूएलबी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। साथ ही, कारीगरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए जाने हेतु लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए।

सीएम धामी ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेकथ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री धामी ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेकथ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गये थे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा बौखनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से मुख्यमंत्री भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर किए जाने की कार्यवाही करने की घोषणा की साथ ही मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेंवला-ब्रह्मखाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने, बौखनाग टिब्बा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने व स्यालना के निकट हेलीपैड का निर्माण करने की घोषणा की।

एनीडए को मिलेगा पूर्ण बहुमतः डिप्टी सीएम

खत्म हो जाएगी भ्रष्टाचार-परिवारवाद की राजनीति

मधुबनी। जिले के झंझारपुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार को सुपौल जिला मुख्यालय स्थित एक रिजॉर्ट में एनडीए कार्यकताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल हुए सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकताओं से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। वही सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जम कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाति और वर्ग के नाम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति ने बिहार को काफी पीछे धकेल दिया। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब विकास के साथ पर आगे बढ़ चुका है।विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ बीमारियां महामारी

का रूप धारण कर चुकी थी, जिसे हमने हटाया। कुछ छिटपुट बीमारी बची हुई है। जब बिहार में हमें बड़ी ताकत मिलेगी, उसे भी खत्म कर देंगे। जो लोग ऐसी बीमारी को फैलाने में सहयोग करते हैं, उन पर रोक लगाने का सही समय आ गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि परिवारवाद को बचाने के लिए आम लोगों के पीछे छिपने वालों को किनारे लगाने की जरूरत है। समाज का जो वर्ग हमसे दूर है, उसे भी जोड़ कर एनडीए को मजबूत करना है। आगामी चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगा। लेकिन हमें दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना है। क्योंकि सरकार जितनी मजबूत होगी, विकास भी उतना ही तेज होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अभी कोसी के इलाके में मिट्टी खनन को अनुमति देने की मांग की है। हालांकि मैंने पहले ही सूबे के सभी डीएम को खेत से निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन करने पर रोकटोक नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना है और किसी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि व्यावसायिक उपयोग होने पर टैक्स देना होगा। कोसी के इलाके की स्थिति थोड़ी अलग है। इस पर जिलाधिकारी से विशेष चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे पूर्व सूबे के पीएचईडी मंत्री सह छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कोसी-मेची लिंक परियोजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि 7500 करोड़ की नदी जोड़ो परियोजना से बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ की समस्या से निजात पाएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम से कोसी तटबंध के इलाके में मिट्टी खनन को छूट देने की अपील की। कहा कि गाद के रूप में जमा यह मिट्टी बाढ़ की समस्या को भी गंभीर करती जा रही है। नदी के बीच बालू नहीं है। इस रेतीली मिट्टी पर खेती भी मुश्किल है। ऐसे में अगर खनन को छूट मिलती है तो गाद की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। उन्होंने विशेष तौर पर सुपौल जिले के विकास के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रयासों की सराहना की। इधर, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के दौरे में बिहार और विशेष तौर पर कोसी के इलाके को कई सौगात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पीएम की सभा में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने अपील की। कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बूथ स्तर तक एनडीए की एकजुटता जरूरी है। कार्यक्रम को सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक अनिरुद्ध यादव, रामविलास कामत, विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हारुण रशीद, एनडीए जिला संयोजक नागेंद्र नारायण ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, संतोष प्रधान, विजय शंकर चौधरी आदि ने भी संबोधित किया।

बात का बना बतंगड़, फिर शुरू हुई मारपीट, 3 घायल

मोतिहारी । चांदमारी मुहल्ले में मंगलवार देर रात दो गुटों के बीच हुई आपसी झड़प में तीन युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक गोलू (20) ने बताया कि वह कोर्ट से लौटकर मंगलवार रात करीब 10 बजे घर में आराम कर रहा था। इसी बीच किसी अनजान नंबर से फोन आया और उसे बाहर बुलाया गया। बाहर निकलते ही कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। गोलू का आरोप है कि साजिद ने अपने भाई खालिद के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। दूसरी ओर, साजिद हुसैन का कहना है कि वह अपने दोस्तों के साथ गोलू के घर के

सामने से गुजर रहे थे, तभी गोलू ने उन्हें तेज आवाज में बात करने पर टोका। जब उन्होंने बात खत्म करने की कोशिश की, तो उन पर हमला कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर अरढ खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। पुलिस का कहना है कि फिलहाल चांदमारी मुहल्ले में शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

मुजफ्फरपुरः आधा दर्जन सिलेंडर ब्लास्ट

मुजफ्फरपुर। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव नगर चौराहा में बुधवार सुबह एक भुजा की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर स्थानीय लोगो की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगो ने मामले की जानकारी सदर थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जहां अग्निशमन टीम के साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे रहे। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि जिसपक काबू पाने में 2 घंटे का समय लगा। चश्मदीदों के मुताबिक, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक आधा दर्जन सिलेंडर फट

गए। हादसे में चार से पांच दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। पीड़ित दुकानदार सुरेन्द्र साह, मुंदिर भगत और सुजल राज ने बताया कि वे वर्षों से यहां खाद्य सामग्री की दुकान चला रहे थे। सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जब तक वे मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी दुकानों का सारा सामान जल चुका था। पीड़ित दुकानदार सुरेन्द्र साह ने बताया कि वो पिछले 15 साल से यहां फास्ट दुकान का दुकान चलाता है। आज सुबह उसे फोन से जानकारी मिली कि दुकानें आग लगा गया है। जिसके बाद वो मौके आपे पहुंच है। दुकान में रखा सभी समान जलकर राख हो गया है। पीड़ित दुकानदार मुंदिर भगत ने बताया कि बीते चार साल से उसका कचरी और नाश्ता का दुकान था। आज उसको फोन से जानकारी मिली कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण दुकान ने आग लग गई है। जबतक वो मौके पर पहुंचा, दुकान जलकर राख हो गया है। पीड़ित दुकानदार सुजल राज ने बताया कि पिछले दो साल से उसका समोसा जलेबी का दुकान था। आज सुबह मकान मालिक फोन कर बताए कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के आक्रमण दुकान में आग लगा गया है। जबतक वो मौके आपे पहुंच, तब स्थानीय मुखिया भोला राय ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग लग गया। दमकल की तीन गाड़िया मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अब स्थिति कंट्रोल में है। मौके पर पहुंचे सदर थाना के दारोगा शंभू कुमार ने बताया कि हमलोग को सूचना मिली कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग लगी है। हमलोग मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। अब आग पर काबू पा लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर जगे अधिकारी

वैध चालान नहीं देने पर भरने पड़ेंगे 25 गुना जुमार्ना

पटना। सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सुपौल के अतिथि गृह में कृषि तथा खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सूबे के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान डिप्टी सीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी से फसल क्षति तथा बीज वितरण के संदर्भ में जानकारी ली। साथ ही उन्हें कृषि विभाग के सब्सिडी धारक और कर्मी की बैठक करने तथा टास्क फोर्स की नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया।डिप्टी सीएम ने पौधा संरक्षण योजना की भी जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। वही मिट्टी जांच प्रयोगशाला के कार्यों से संबंधित समीक्षा के क्रम में उन्होंने किसानों के बीच जागृति फैलाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने उर्वरक के सही खपत का आंकलन कर प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यानिक फसल जैसे- आलू, मेंथा, खस, लेमन ग्रास आदि उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।वही खनन विभाग की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम ने सहायक निदेशक खनन को अवैध खनन और परिवहन पर पूर्ण रोकथाम लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा निर्माण से संबंधित सभी कार्य विभागों को अपने विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में वैध चालान से ही खनिज आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध 25 गुना दंड वसूले जाएँ। वही सहायक निदेशक खनन को कार्य विभागों में संवेदक द्वारा इस्तेमाल किए गए लघु खनिज चालान के जांच के निर्देश दिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम ने बताया कि साधारण मिट्टी के निजी उपयोग पर कोई रॉयल्टी नहीं वसूली जाएगी। इसका प्रचार प्रसार माइकिंग से करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि अगर रैयतों द्वारा मिट्टी की बिक्री अथवा व्यवसाय किया जाता है तो उनसे रॉयल्टी की वसूली की जाएगी। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जैसे बसंतपुर छातापुर, निर्मली, मरौना, किशनपुर और सुपौल में रैयती भूमि पर बालू, धुस मिट्टी अथवा गाद जमा होने का सर्वे करने का निर्देश दिया। बैठक में अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

आंधी-बारिश से क्षतिग्रस्त 500 घरों का मिला आवेदन

नालंदा। गत सप्ताह 10 अप्रैल गुरुवार की शाम नालंदा जिले में आई प्रचंड आंधी-बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 22 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि सैकड़ों घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। आपदा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जिलेभर से गृह क्षति के एवज में मुआवजा के लिए कुल 500 आवेदन प्राप्त हुए थे। स्थलीय निरीक्षण और जांच के बाद इनमें से 477 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। प्रभावित परिवारों को आपदा राहत के तहत लगभग 29 लाख 79 हजार रुपए का मुआवजा वितरित किया जाएगा। आंधी-पानी में जान गंवाने वाले सभी 22 मृतकों के आश्रितों को 4.24 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक प्रकोप

बिहारशरीफ प्रखंड क्षेत्र में देखा गया। इस क्षेत्र से गृह क्षति के लिए सर्वाधिक 264 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को लगभग 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।] घरों के नुकसान के मामले में गिरियक प्रखंड दूसरे स्थान पर है, जहां 84 घरों को तेज आंधी के कारण हानि पहुंची है। इनमें चार पशुशेड और पांच मुर्गी फार्म भी शामिल हैं। गिरियक के प्रभावित निवासियों को करीब तीन लाख 98 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। रहुई प्रखंड तीसरे स्थान पर है, जहां 58 घरों को आंधी-बारिश से क्षति हुई है। इसी प्रकार नूरसराय में 38 मकानों को तेज हवा से नुकसान पहुंचा है।

हमारा गठबंधन सबसे बेहतर, विपक्ष डरा हुआ है : मंत्री ललन सिंह

मुजफ्फरपुर। जिले में एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक में जदयू नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हुए। बैठक में ललन सिंह के अलावा बिहार सरकार में मंत्री संजय झा, नितिन नवीन और कई दूसरे नेता मौजूद रहे। ललन सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोग भी देखें हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े और विश्वसनीय उभरते हुए अर्थव्यवस्था में से एक हैं। हमने कई क्षेत्रों में आर्थिक रूप से प्रगति हासिल की है। हमारे गठबंधन ने सबसे ज्यादा और बेहतर काम किया है। इस काम से विपक्षी दलों के लोगों को परेशानी हो रही है।बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता नितिन नवीन ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की मिथिला की धरती पर रैली होनी है। बिहार को कई सौगात मिलेगी

और बिहार को जिस प्रकार से सौगात मिल रही है, इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। हम 12 महीने काम करने वाले लोग हैं और काम करते रहेंगे। बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और इसमें इसके लिए पूरी तैयार है।बिहार में हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नाराज होता है तो हम उन्हें मना लेते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। जीतनराम मांझी वरिष्ठ और गार्जियन हैं, वो हम सबके साथ में हैं और आगे भी हम सब साथ रहेंगे। विपक्ष पर हमला करते हुए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा, विरोधी दल के लोग और नेता विरोधी बरसाती मेढक की तरह हैं। ये लोग चुनाव आते ही अलग-अलग दांव खेलते हैं और सभी गांव में फेल हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव इसका प्रमाण है। हमारा गठबंधन सबसे मजबूत और बेहतर है। हम 365 दिन आम आदमी के बीच में रहने वाले लोग हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उसका निराकरण भी करते हैं।

नीतीश पर की गई ममता बनर्जी की टिप्पणी पर जेडीयू का पलटवार

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान

पटना/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज जो हालात बने हुए हैं, उसके लिए ममता बनर्जी का गैरजिम्मेदाराना बयान एवं कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने में असफल रहने की वजह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लोगों की हत्याएं, आगजनी एवं हिंसा की घटनाओं ने भयभीत लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया है। जो बंगभूमि कभी कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों से गुंजायमान हुआ करता था, घृणा, वैनस्य एवं हिंसा काजी नजरुल इस्लाम की पंक्तियों से गुंजायमान हुआ करता था, घृणा, वैमनस्य एवं हिंसा का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का शासन इससे निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। दूसरी तरफ बिहार में अमन चैन और शांति है। यहां बीस वर्षों के नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ और न ही कभी कर्फ्यू लगा। यहां सभी धर्म और जाति को समानता के

साथ देखा जाता है। ममता बनर्जी का बयान कि नीतीश जी थोड़े से पॉवर के लिए एनडीए के साथ खड़े हैं, केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सत्ता का अर्थ सेवा है, जो वह सभी वर्गों की समानभाव से करते रहे हैं।

संक्षिप्त डायरी

नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में किया बड़ा फेरबदल

पटना/ भव्य खबर । बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 334 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया है। इसमें तीन जिलों के सिविल सर्जन समेत 65 चिकित्सा पदाधिकारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डॉ. विनोद कुमार चौधरी को नवादा, डॉ. दीपक कुमार को शिवहर और डॉ. राजकुमार चौधरी को किशनगंज का सिविल सर्जन बनाया गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उपाधीक्षक डॉ. अमित कुमार झा को बनाया गया है। यह स्थानांतरण अगले आदेश तक के लिए किया गया है। डॉ. नीता अग्रवाल, जो पहले नवादा में असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं, उन्हें अब स्वास्थ्य विभाग, पटना में अपर निदेशक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। डॉ. देवदास चौधरी, जो शिवहर में असैनिक शल्य चिकित्सकसह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे, अब मुंगेर में क्षेत्रीय उप निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। डॉ. राजेंद्र चौधरी, अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआं, पटना, को स्वास्थ्य विभाग, पटना में अपर निदेशक बनाया गया है। डॉ. राज कुमार चौधरी, सह प्राध्यापक, ई.एन.टी. विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया, को किशनगंज में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिसूचना में सभी स्थानांतरित चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने नए पदस्थापन स्थान पर तुरंत योगदान करें। सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि यदि चिकित्सकों का पदस्थापन अतिरेक हो जाता है, तो उन्हें तत्काल मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) में योगदान करने की व्यवस्था करें।

पीएम की रैली में जिले से 50 हजार एनडीए कार्यकर्ता जाएंगे मधुबनी

पटना/ भव्य खबर । मुजफ्फरपुर । 24 अप्रैल को मधुबनी में होनेवाली पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में मुजफ्फरपुर से पचास हजार एनडीए कार्यकर्ता जाएंगे। इसके लिए जदयू व भाजपा ने कमर कस ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दौड़े के बाद मंगलवार को जदयू के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह व पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद संजय झा ने गोबरसही स्थित एक होटल में एनडीए कार्यकताओं के साथ बैठक कर उन्हें आमंत्रित किया। अध्यक्षता भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, संचालन जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा व धन्यवाद ज्ञापन भाजपा पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि ललन सिंह ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास पीएम का मूलमंत्र है। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहे है। संजय झा ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बेहतरीन समन्वय के साथ राज्य व केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2029 तक बिहार में विकास की गति तेज रहेगी। डबल इंजन सरकार का भरपूर फायदा मुजफ्फरपुर से 11 विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। विरोधी के हाथ में एक भी सीट नहीं लगानी चाहिए। मौके पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, राजू कुमार सिंह, संगठन संयोजक चंदन सिंह, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, एलएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, विधायक अशोक सिंह, अरुण सिंह, अशोक चौधरी, अभिषेक झा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अजीत कुमार, महेश्वर यादव, रॉबिन सिंह, शैलेश शैलू, मनोज कुशवाहा, शिशिर नीरज व अनीश कुमार आदि थे। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर राजपूत समाज ने जताया आक्रोश बक्सर। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर जिला राजपूत समाज ने मंगलवार को शहर के गोलंबर से आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च यमुना चौक, सत्यदेवगंज होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंच संपन्न हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व जोगेंद्र सिंह एवं संचालन कृष्णा सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हिंदू समाज के आदर्श वीर शिरोमणि राणा सांगा पर अमर्यादित बयान देते हुए उनको गद्दार एवं उनके वंशजों को गद्दार कहा है। आक्रोश मार्च के माध्यम से राजपूत समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राज्य सभा की सदस्यता समाप्त करने व किसी भी महापुरुष पर अमर्यादित बयान और टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने को मांग पत्र डीएम के माध्यम से सौंपा। उन्होंने कहा कि सांसद मे बैठकर महापुरुषों पर अमर्यादित ब्यान देना देश के लिए शर्म की बात है। जिसे राजपूत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बक्सर जिला राजपूत समाज ने बक्सर गोलंबर से बाबू वीर कुंवर सिंह चौक तक आक्रोश मार्च निकालकर ऐसे लोगों के प्रति अपना विरोध जताया।

25 से 30.. फिर से नीतीश! पोस्टर लगाकर क्यों करनी जेडीयू को काउंटर अटैक

पटना/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीएम पद को लेकर घमासान मचा है। अब जेडीयू ने पोस्टर के जरिए काउंटर अटैक किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पटना में अपने ऑफिस के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में लिखा है, '25 से 30, फिर से नीतीश'। इसका मतलब है कि जेडीयू दावा कर रही है कि 2025 से 2030 तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनेगी। इस पोस्टर से जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम पद को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि कन्फ्यूजन के हालात बन गए। बिहार में चुनाव का माहौल गरमा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दल पहले ही कह चुके हैं कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन, बीच-बीच में कुछ नेताओं के बयानों से शक पैदा हो जाता है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा। इससे एनडीए में हलचल मच गई थी। जेडीयू के नेता सैनी के इस बयान से नाराज दिखे। बाद में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह तक कहना पड़ा कि नीतीश आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बीच बुधवार को बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल थे। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी जाने वाले हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए ये नेता नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में पीएम के साथ रहेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। जेडीयू ने पोस्टर लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं और वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। लेकिन, बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये है कि चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। मगर, राजनीति में जो दिखता वो होता नहीं।

एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि

समाज को प्रगति की दिशा में भी ले जाता है - सीएम सैनी

36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी ड्राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के 13 देशों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित

चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग तैयार करते समय केवल कानून की भाषा ही नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं, जरूरतों और संभावनाओं पर भी विचार करना आवश्यक है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि समाज को प्रगति की दिशा में भी ले जाता है। इसलिए विधायी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, समानता और नागरिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि नीति निर्माण और कानून निर्माण की प्रक्रिया समावेशी और सशक्त हो। ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य ने प्रशासन में पारदर्शिता लाई है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब विधायी प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक, समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा विधानसभा में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किए जा रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस पहल में 13 देशों के कुल 28 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी उपस्थित थे।

विधान ड्राफ्टिंग केवल एक तकनीकी कार्य नहीं, यह एक दूरदर्शी प्रक्रिया

नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अपनी विधायी प्रणाली पर बहुत गर्व है, जिसने सामाजिक न्याय, समावेशिता और पारदर्शिता में निरंतर मिसाल पेश की है। विधायी ड्राफ्टिंग केवल एक तकनीकी कार्य नहीं, यह एक दूरदर्शी प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन की भावना को मूर्त रूप देती है, संवैधानिक मूल्यों को कायम रखती है और लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायी ड्राफ्टिंग एवं अनुसंधान संस्थान का आदर्श वाक्य है ह्यप्रारूपण ज्ञानम अभ्यासेन शोभतेह्ण अर्थात सही ड्राफ्टिंग के लिए निरंतर अभ्यास और ज्ञान जरूरी है। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी अवधारणा पर आधारित है।

हरियाणा ने डिजिटल विधायिका स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने इस दिशा में सदैव पहल की है। पारदर्शी और उत्तरदायी विधायी प्रणाली के निर्माण के लिए हमने विभिन्न तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने डिजिटल विधायिका की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे विधायकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है और आम जनता तक सूचनाओं की पहुंच भी आसान हुई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

विधान ड्राफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक औपचारिक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच आपसी समझ, ज्ञान के आदान-प्रदान और विधायी पारदर्शिता की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह मंच हमारे अनुभवों को साझा करने, एक-दूसरे की विधायी प्रणालियों को समझने और अपने-अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाने का माध्यम है। आज जब विभिन्न देशों के प्रतिभागी एक साथ आए हैं, तो यह वैश्विक सहयोग और साझेदारी का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत के ह्लवसुधैव कुटुम्बकम्ह्व के शाश्वत दर्शन- दुनिया एक परिवार है, को और मजबूत करते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विधायी विधायी ड्राफ्टिंग की बारीकियों, प्रक्रियाओं, संवैधानिक ढांचे और व्यावहारिक उदाहरणों से परिचित कराना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम में साझा किए गए ज्ञान और अनुभव प्रतिनिधिगणों के संबंधित देशों की विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की यात्रा केवल एक औपचारिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक स्थायी दोस्ती की शुरूआत है। उन्होंने हरियाणा के लोगों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब आप अपने देशों में लौटेंगे, तो आप अपने साथ भारत और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, मित्रता, अतिथि सत्कार और सुखद अनुभवों की छाप अपने साथ लेकर जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।

संक्षिप्त डायरी

पलवल में भाजपा नेता का फोन हैक करके लाखों ठगे

पलवल/ भव्य खबर। जिले में साइबर अपराधियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के बैंक खाते से 32 लाख 46 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हुडा से टर-2 के मुकेश सिंगला का मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित नेता ने बताया कि उन्होंने अभी तक नेट बैंकिंग की सुविधा शुरू नहीं की थी। साइबर अपराधियों ने उनके फोन को हैक कर बैंक के सभी मैसेज दूसरे नंबरों पर डायवर्ट कर दिए। इसके बाद खाते का पासवर्ड बदलकर क्रेडिट कार्ड के जरिए सात अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पीड़ित को ट्रांजे शन के मैसेज मिले, उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क किया। बैंक ने उन्हें कस्टमर केयर से संपर्क करने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीड़ित का आरोप है कि बैंक ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि पैसे किन-किन खातों में ट्रांसफर किए गए। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि पैसा किन खातों में ट्रांसफर किया गया। जल्द ही आरोपियों को गिर तार किया जाएगा।

अवैध निमार्णों पर चला पीला पंजा, महिलाओं ने किया विरोध

फरीदाबाद / भव्य खबर। से टर 87 बीपीटीपी इलाके में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने सड$क किनारे अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। महिलाओं ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए। उनका कहना था कि वे पिछले 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास मकानों की रजिस्ट्री भी है। उन्होंने शिकायत की कि न तो कोई नोटिस मिला और न ही मुआवजा दिया गया। तोड$फोड़ के दौरान कुछ महिलाएं अपना सामान बचाने की कोशिश में पुलिस से भिड़ गईं। पुलिस ने उन्हें धके मारकर बाहर निकाला। इस दौरान कुछ महिलाएं बेहोश भी हो गई। एचएसवीपी के जेई नरेश ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि 45 फुट के मास्टर रोड के साथ 14 फुट का सर्विस रोड है। लोगों ने इस रोड पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जो रजिस्ट्री है, वह दूसरे खसरा नंबर की है। पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए यह कार्रवाई करनी पड़ी।

शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर ठगी, तीन गिर तार

फरीदाबाद / भव्य खबर। शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करने के मामले मे साइबर थाना एनआईटी की टीम ने तीन आरोपियों को गिर तार किया है। पुलिस प्रवता ने बुधवार को बताया कि चार्मवुड विलेज सुरजकुंड रोड फरीदाबाद के रहने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, जहां इंवेस्टमेंट की टिप्स दी जाती थी। शिकायतकर्ता ने भी इंवेस्टमेंट करने को कहा। इसके बाद उसने विभिन्न ट्रांजे शन के माध्यम से कुल छह लाख 16 हजार रू ठगों के खाता में भेजे। जिस निवेश के बदले में शिकायतकर्ता को पैसा वापिस नही दिया गया। जिसकी शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साइबर थाना एनआईटी की टीम ने आरोपी सुरेश (32) निवासी गांव नायन, जयपुर, विजय परसोया (28) गांव लिसाडिया, सीकर हाल ग्रीन पार्क कालोनी, जयपुर व विजय शान्तव (32) निवासी जमुनापुरी कॉलोनी जयपुर राजस्थान को जयपुर से गिर तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुरेश खाताधारक है और इसने अपना खाता विजय शान्तव को दिया था और.विजय शान्तव को आगे खाता विजय परसोया को दिया था। जिसने खाता आगे ठगों को दे दिया था। आरोपी सुरेश के खाता में मामले से जुड़े दो लाख रुपए आये थे। आरोपियों को बुधवार अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

गर्मी को लेकर हाई अलर्ट हुई फायर ब्रिगेड

फरीदाबाद / भव्य खबर। फरीदाबाद में गर्मी के मौसम और फसल कटाई के दौरान आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। विभाग ने सभी फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। से टर-25 स्थित फायर स्टेशन के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में छह फायर स्टेशन हैं। इनके पास 28 फायर ब्रिगेड गाडियां और छह बाइक तैनात हैं। सभी गाडियां 24 घंटे तैयार रहते हैं। किसी भी आपात स्थिति में टीमें तुरंत मौके पर पहुंचती हैं। विभाग इस समय अग्नि शमन सप्ताह मना रहा है। इसके तहत स्कूल-कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को गर्मी के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। खेतों में फसल कटाई और औद्योगिक क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही नजदीकी फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंचती है। जरूरत पडने.पर अन्य फायर स्टेशनों से भी अतिरि त गाडियां मंगवाए जाते हैं। विभाग का मु य लक्ष्य आगजनी की घटनाओं को रोकना और लोगों को सुरक्षित रखना है।

चोरी का एल्युमिनियम स्क्रेप खरीदने वाला कबाड़ी दबोचा, चार लाख बरामद

फरीदाबाद / भव्य खबर। चोरी का एल्युमिनियम स्क्रैप खरीदने वाले कबाड़ी को पुलिस ने गिर तार कर उसके कजे से चार लाख रुपए बरामद किए है। मामले में तीन आरोपी नासीर हुसैन, श्रवण व सागर को पहले ही गिर तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस प्रवता ने बुधवार को बताया कि विष्णु निवासी से टर-9 फरीदाबाद ने पुलिस चौकी संजय कॉलोनी से टर-23 में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका सरुरपुर फ्रेंडस कपलैस में एल्युमिनियम स्क्रैप का गोदाम है। 16 दिसंबर को गोदाम में करीब 42 टन स्क्रेप खाली हुआ था, 17 दिसबर को देखा तो गोदाम से 15 से 20 टन स्क्रेप चोरी हुआ मिला, जिस शिकायत पर थाना मुजेसर में चोरी से संबंधित धाराओ मे मामला दर्ज किया गया। अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साहजाद खान(45) निवासी डबुआ कालोनी फरीदाबाद को सोहना टी प्वांइट एरिया से काबू किया है। आरोपी से पुछताछ में सामने आया कि वह कबाड का सामान खरीदने का काम करता है और उसका एक कबाड का गोदाम भी है। उसने एल्युमिनियम स्क्रेप आरोपी नासीर हुसैन से खरीदा था।

विकास कार्यो में न बरती जाए कोई कोताही : ए मोना श्रीनिवास

फरीदाबाद / भव्य खबर। नगर निगम कमिशनर ए मोना श्रीनिवास ने बुधवार को निगम के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं ।उन्होंने हरियाणा सरकार के आगामी 15 जून तक सभी नालों की सफाई और सड$क की मर मत के भी दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि बारिश के समय से पहले ही आगामी 15 जून तक सभी ड्रेनेज की सफाई करना सुनिश्चित किया जाए । ताकि बरसात के दिनों में शहरवासियों को कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। बैठक में एडिशनल कमिशनर स्वप्निल रवीन्द्र पाटिल, ओल्ड नगर निगम जोन से जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार ,एनआईटी जोन के जॉइंट कमिश्नर हितेंद्र कुमार ,जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ करण भदौरिया के अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच से अधिकारी मौजूद रहे।

गुरुग्राम के पटौदी में होटल मालिक की गोली मारकर हत्या

गुरुग्राम/ भव्य खबर/ एजेंसी। पटौदी के जाटौली में बदमाशों ने होटल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस वारदात में होटल मालिक की मौके पर मौत हो गई। बदमाश होटल में कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने घुसे थे और मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। गोलियों की आवाज सुनकर होटल के कर्मचारी और अन्य लोग आए, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही पटौदी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वहां लगे सीसीटीवी भी खराब पाए गए। मृतक की पहचान जाटौली निवासी दीपेंद्र उर्फ मोनू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या की यह वारदात मंगलवार देर रात की है। पुलिस मामले को रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। कई वर्ष पहले जाटौली गांव में इंद्रजीत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में मोनू के भाई का नाम सामने आया था। पुलिस इस हत्याकांड की जांच इंद्रजीत मर्डर केस से भी जोड़कर कर रही है।गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दीपेंद्र उर्फ मोनू का पटौदी-कुलाना रोड पर होटल है। बदमाशों ने मंगलवार देर रात वारदात को अंजाम दिया उस समय होटल में भीड़ भाड़ नहीं थी। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर वे खराब पाए गए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आस पास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि हत्यारों की पहचान हो सके।

मिनी बस पलटी, दो बच्चे घायल, लोडिंग टैंपो द्वारा टक्कर मारने से हुआ हादसा

गुरुग्राम/ भव्य खबर । स्कूल की मिनी बस बुधवार सुबह दूसरे वाहन की ट कर से पलट गई। हादसे में दो बच्चे घायल हो गए। बस पलटते ही बच्चे चिल्लाने लगे तभी आस-पास के लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को घर भेज दिया। घटना सुबह से टर-69 चौक ट्यूलिप स्क्वायर के पास हुई। बच्चों को लेकर बस चौराहे के पास खड़ी हुई थी तभी एक लोडिंग टैंपो ने आकर बस में जोरदार ट कर मार दी। ट कर लगने के कारण बस के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। ड्राइवर की मदद से बच्चों को बस से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इसी दौरान टैंपों का चालक फरार हो गया। स्कूल प्रबंधन ने घटना पर खेद जताया है। स्कूल प्रिंसिपल सजिता अय्यर ने कहा कि यह बस स्कूल की नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच कराएंगे।

बाजार में अब नहीं लगेगा जाम, गुप्ता होटल के पास रास्ता किया बंद

फरीदाबाद/ भव्य खबर । मोहना रोड पर पिछले 6 महीने से एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके चलते मंगलवार को गुप्ता होटल से मैन बाजार की ओर आने वाले रास्ते और बल्लभगढ़ अनाज मंडी की मुख्य सड़क को बड़े-बड़े पत्थर लगाकर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया । इसके अलावा अगर किसी को आंबेडकर चौक से बाजार के अंदर आना व जाना है, तो उसको राजकीय कन्या स्कूल के सामने से यू टर्न लेकर आना होगा । क्योंकि अग्रवाल चौक को भी बंद कर दिया है। मोहना रोड पर अक्टूबर से एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह निर्माण कार्य आदर्श नगर थाने से लेकर सिटी पार्क के पास तक चल रहा है। कुछ समय चंदावली चौक पर बड़े-बड़े पत्थरों को लगाकर मोहना रोड पर जाने वाले भारी वाहनों को बंद कर दिया था । वहीं अब मैन बाजार में गुप्ता होटल से जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। अब मैन बाजार में जाने वाले बड़े वाहनों को बंद कर दिया है ताकि बाजार में बड़े वाहनों की वजह से जाम की समस्या न हो। बड़े वाहनों की एंट्री बंद होने से अब लोगों को बाजार में जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। आकाश सिनेमा के साथ से बल्लभगढ़ मंडी जाने वाले रास्ते को भी मंगलवार को बंद कर दिया है। इस रास्ते से जहां आम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। वहीं इन दिनों मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन अब रास्ता बंद होने की वजह से किसान मंडी में नहीं आ पा रहे हैं। मंडी के सचिव इंद्रपाल ने बताया मोहना रोड चल रहे निर्माण कार्य के चलते किसानों उनकी मंडी में फसल लेकर नहीं पहुंच पा रहे है। पहले किसान जैसे तैसे करके आ जाते थे, लेकिन मंगलवार को अनाज मंडी को आने वाले मुख्य रास्ते को ही बंद कर दिया है।

गुरुग्राम के नामी अस्पताल में इलाज कराने गई थी एयर होस्टेस, 'कोई आरोप साबित नहीं': मेदांता अस्पताल

गुरुग्राम/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान एयर होस्टेस के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर उस समय यौन उत्पीड़न किया, जब वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी. दरअसल गुरुग्राम के सदर थाने में 46 साल की पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 6 अप्रैल को तबीयत खराब होने के चलते उसके पति ने उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया था. जहां पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. इसी दौरान उसे आभास हुआ की उसके साथ अश्लील हरकत की जा रही है.

'कोई आरोप साबित नहीं'

मेदांता अस्पताल ने सोमवार को एक बयान जारी कर आरोपों की बात को स्वीकार किया और कहा कि अस्पताल जांच में पूरा सहयोग कर रहा है. सीसीटीवी फुटेज और महिला की मेडिकल फाइलें पुलिस के साथ शेयर की गई हैं. उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में कोई आरोप साबित नहीं हुआ है. वहीं गुरुग्राम पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप ने मीडिया को बताया कि सदरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

अस्पताल में भर्ती एयर होस्टेस से अश्वील हरकत

बेहोशी की हालत में होने की वजह से वह न तो इसका विरोध कर पा रही थी और न ही शोर मचा पा रही थी. पीड़िता के मुताबिक, हालात में सुधार के बाद 13 अप्रैल को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. घर पहुंचते ही एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत 112 नंबर पर की और फिर अपने लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई.

शिकायत में एयर होस्टेस ने क्या कहा?

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह एक एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस है. कंपनी की तरफ से गुरुग्राम में वह ट्रेनिंग के लिए आई थी. वह एक होटल में रुकी थी. होटल में स्विमिंग के दौरान पानी में डूबने से उसकी तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद इलाज के लिए वह एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी. इसके बाद उसके पति ने 6 अप्रैल को उसे इलाज के लिए गुरुग्राम में ही एक अन्य हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. 13 अप्रैल को अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया.

वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, हुई छेड़छाड़

शिकायत में एयर होस्टेस ने कहा है कि 6 अप्रैल को इलाज के दौरान वह वेंटिलेटर पर थी, तभी अस्पताल के किसी स्टॉफ ने उसका यौन उत्पीड़न किया. वेंटिलेटर पर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई लेकिन बहुत डरी हुई थी. घटना के समय वह बेहोशी की हालत में थी. डिस्चार्ज होने के बाद उसने अपने पति को साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया. उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी और फिर लीगल एडवाइजर के सामने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश

पुलिस पीआरओ के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस अस्पताल स्टाफ से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर गंभीरता से जांच कर रही है.

20 साल से पंचायती जमीन पर बसे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक: मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। हरियाणा के उन लोगों के लिए अच्छी खबर आई है, जो पंचायती जमीन पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं. पानीपत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ऐलान करते हुए कहा गया कि पंचायती जमीन पर 500 वर्ग गज के क्षेत्र में बने मकानों में 20 सालों से रह रहे लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पानीपत की गीता यूनिवर्सिटी के हॉल में गांव नौल्था, नौल्था डुगरान और आसन की पंचायतों को संबोधित करते हुए घोषणा की गई कि ग्राम पंचायत की भूमि पर 500 वर्ग गज तक के 20 साल पुराने मकान के मालिकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रयासरत है. गांव में तालाबों और फिरनी का सौंदर्यकरण किया जाएगा और तालाबों में साफ पानी भरा जाएगा, ताकि पशुओं को पीने का साफ पानी मिल सके.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है. इस दौरान उन्होंने विभिन्न लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें प्राथमिकता से समाधान करवाने का आश्वासन दिया. प्रदेश के पंचायत खनन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ई- लाइब्रेरी बनाई जाएगी और सभी गांव के बाहर शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा. श्मशान घाट पहुंचने वाले रास्तों को पक्का बनाया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी.

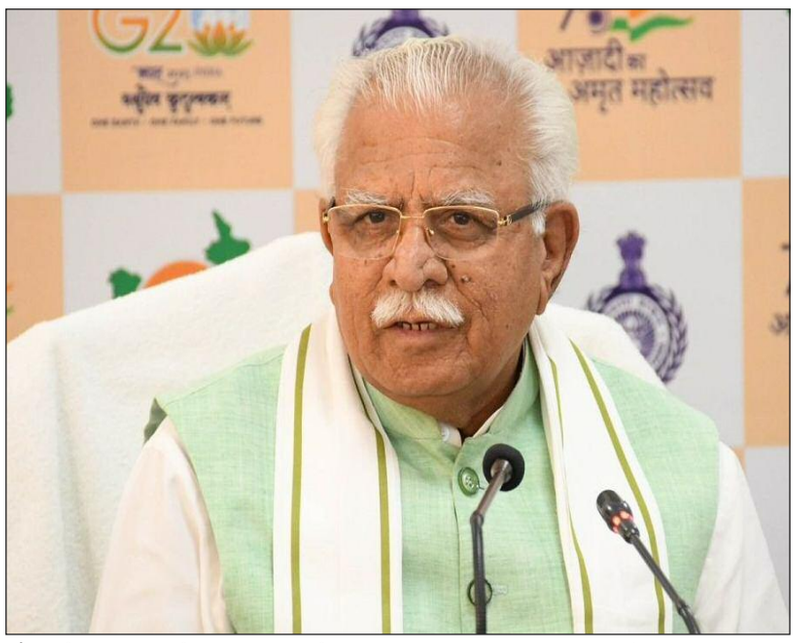

विरोध के चलते एक माह से बंद पड़ा कचरा प्रसंस्करण प्लांट

फरीदाबाद / भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। प्रतापगढ़ गांव में स्थापित कचरा पृथक्करण और प्रसंस्करण प्लांट ग्रामीणों के विरोध के चलते नासूर बन गया है। विरोध के चलते करीब एक माह से प्लांट ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में प्रतिदिन निकल रहे कचरे को बंधवाड़ी भेजा जा रहा है। ऐसे में करोड़ों के संयंत्र का उपयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर, प्रतापगढ़ समेत आस-पास के गांव और कालोनीवासियों का विरोध जारी है। शहर में प्रतिदिन 1000 टन नागरिक कचरा उत्पन्न होता है। वर्षों से शहर कचरा निपटान संकट से जूझ रहा है। नगर निगम फरीदाबाद की ओर से प्रतिदिन 350 टन क्षमता वाला प्रतापगढ़ कचरा पृथक्करण और प्रसंस्करण प्लांट एक वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इस दौरान प्रतापगढ़ गांव, राजीव कॉलोनी और सेक्टर-56 के निवासियों ने कचरा पृथक्करण और प्रसंस्करण प्लांट का विरोध शुरू कर दिया। विरोध के बीच फरवरी 2025 में दोबारा से इस प्लांट को शुरू किया गया। इस बीच ग्रामीणों और सेक्टरवासियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। 12 मार्च को विरोध के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ 10 ट्रक ठोस अपशिष्ट पदार्थ को प्रसंस्करण के लिए डाला गया। विरोध के बीच प्लांट पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। एक माह से करोड़ों की लागत से बना संयंत्र ठप पड़ा है। ऐसे में शहर से निकलने वाले कचरे को निगम की ओर से अन्यत्र कहीं और भेजना पड़ रहा है।

प्रतापगढ़ पृथक्करण एवं प्रसंस्करण प्लांट की दीवार राजीव कॉलोनी से सटी है। कुछ दूरी पर प्रतापगढ़ गांव और सेक्टर-56 है। ऐसे में यहां से कचरे की दुर्गंध से आस-पास के लोगों का रहना मुश्किल है। इससे निवासियों को बीमारियों का भी खतरा है। - दीपक पांचाल, निवासी

प्लांट में एनजीटी के नियमों की पूरी तरह से पालना भी नहीं हो रही है। इसके लिए हमने एनजीटी में अपील कर रखी है। इसकी सुनवाई 16 मई को होनी है। जल्द ही राजीव कॉलोनी, सेक्टर-56 और प्रतापगढ़ गांव के निवासी इसपर आंदोलन करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। - विनोद शर्मा, निवासी शहर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण अलग-अलग प्लांट में किया जाता है। प्रतापगढ़ पृथक्करण एवं प्रसंस्करण प्लांट के लिए वहां के निवासियों से बात चल रही है। उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे यहां के निवासियों को समस्या नहीं होगी। - हितेंद्र शर्मा, संयुक्त आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद

संक्षिप्त डायरी

भाजपा ने अपनी गरीब विरोधी सोच के चलते ईडल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने बंद किए : आदेश भारद्वाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार द्वारा अचानक से ईडल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दिए जाने पर करावल नगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला सरकार की नियत पर सवाल खड़े करता है हमारे समय में इस स्कीम को लागू किया गया था जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी जबकि विश्विद्यालयों में 10 फीसदी आरक्षण तय करता था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले हो रहे हैं या होने जा रहे हैं। सरकार के इस निर्णय ने दिल्ली के हजारों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। साधारण सी बात है कि जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो कोई भी कमजोर वर्ग का व्यक्ति यह कैसे साबित करेगा कि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आदेश भारद्वाज कहते हैं न सिर्फ स्कूल बल्कि इस कोटे के तहत निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित रहते हैं। बिना प्रमाणपत्र उसका इलाज कैसे होगा? सरकार यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकती कि प्रमाणपत्र जारी करने में धांधली हुई है। या धांधली में पूर्व की सरकार को दोष देकर नहीं बचा जा सकता। सीधी सी बात है.. अगर ऐसी कोई धांधली हुई है तो उसकी जांच करवाई जाए। इस तरह के प्रमाणपत्र एस.डी.एम. द्वारा जारी किए जाते हैं। सरकार यह बताए कि कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बनाकर गरीबों से उनका हक छीनना चाहती है। यह एस.टी.एस.सी. और ओबीसी आरक्षण छीनने की शुरूआत है। योंकि आरक्षित वर्ग के लिए बजट में कटौती करके इसका इशारा सरकार पहले ही दे चुकी है, और अब इस तुगलकी फरमान से सीधे सीधे स्कूलों और अस्पतालों को लाभ पहुंचेगा गरीबों को सिस्टम से बाहर कर निजी संस्थानों को लूट की छूट देने का प्रयास है।

सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर थे डॉ.भीमराव अबेडकर : परमानन्द शर्मा

नई दिल्ली (एजेंसी)। डॉ.भीमराव अबेडकर के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। वे केवल दलित वर्ग के ही नहीं अपितु समस्त समाज के हित में सोचते थे और उन्होंने समानता के पक्ष में जोरदार तरीके से आवाज उठाई। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम नगर वार्ड से नगर निगम का चुनाव लड़े परमानन्द शर्मा का। परमानन्द शर्मा नें डॉ.अबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रधा सुमन करते हुए कहा डॉ. भीम राव अबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर थे, उन्होंने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें शिक्षा के माध्यम से जीवन की मु यधारा में लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अबेडकर, जो भारतीय संविधान के निमार्ता थे, जिसे दुनिया भर में एक पवित्र दस्तावेज माना जाता है, ने संविधान में हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ भेदभाव और अन्याय को मिटाने, उन्हें समान और गरिमा के साथ जीवन में आगे बढड़े के समान अवसर देने के प्रावधान किए। परमानन्द शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार संविधान को नष्ट करने तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को कमजोर करने, चुनाव आयोग, संसद में विपक्ष की आवाज सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्षी दलों तथा नेताओं और भाजपा सरकार के उत्पीडड़ तथा कुकृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का व्यवस्थित प्रयास कर रही है। परमानन्द शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता हमेशा भाजपा तथा आरएसएस के नापाक इरादों तथा कुकृत्यों के खिलाफ खड़े रहे हैं तथा देश पर उनके खतरनाक विभाजनकारी कदमों को थोपने के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पहल पर अहमदाबाद में हाल ही में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों की रक्षा तथा उत्थान का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार में समाज की मु यधारा में लाने के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।

निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए ईडल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगायी गयी: आप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडल्यूएस) वर्ग के प्रमाणपत्र बनाने पर रोक को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने साारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों और स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए मु यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने यह निर्णय किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में शासन और प्रशासन चलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। मु यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब राजधानी में ईडलूएस के प्रमाणपत्र नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने चेताया कि इस फैसले का सीधा असर उन छात्रों और मरीजों पर पड़ेगा जो स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में ईडलूएस आरक्षण के तहत लाभ उठाते हैं। 'आप नेता ने कहा, 'सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में 10 प्रतिशत ईडलूएस आरक्षण लागू किया हुआ है। अगर प्रमाणपत्र नहीं बनेंगे तो लाखों छात्रों को दाखिले में मुश्किल होगी। अस्पतालों में भी ईडल्यूएस प्रमाणपत्र के आधार पर इलाज मिलता है, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा।'उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इस 'तुगलकी फरमान से न सिर्फ बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, बल्कि जिन लोगों को नौकरियों में ईडलूएस आरक्षण मिलना था, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर निजी स्कूलों और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'अगर कुछ ईडल्यूएस प्रमाणपत्र गलत बने हैं, तो सरकार बताए कि कितने एसडीएम और डीएम पर कार्रवाई की गई? अपने अधिकारियों की गलती की सजा आम जनता को यों दी जा रही है?

कांग्रेस को धरने का हक, लेकिन जमीन लूटने का नहीं... यह कहते हुए बीजेपी नेता रविशंकर हुए हमलावर

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट दाखिल करने के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा देशभर में किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस को धरने का हक है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं।

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि कांग्रेस ने 'यंग इंडिया लिमिटेड' नामक कंपनी के ज़रिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया। इस कंपनी में 76फीसदी शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 50 लाख रुपये में 90 करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ कर, देश के कई शहरों में स्थित करोड़ों की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले ली गई। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया को गैर-लाभकारी संस्था बताया गया, लेकिन इसका कोई सामाजिक कार्य सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ हो चुकी है और अब कोर्ट में सुनवाई

21 और 25 अप्रैल को होगी।

विरोध प्रदर्शन, कानूनी प्रक्रिया से भागने की कोशिश

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को कानूनी प्रक्रिया से भागने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा, कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर सवाल उठाना गलत है? इसके साथ ही भाजपा ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और किसी भी धरने या विरोध से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यह अखबार कभी आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नेहरू परिवार का निजी मंच और पैसे कमाने का एटीएम बना दिया।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा, कि मैं उनके प्रदर्शन के अधिकार को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन आखिर किस बात के लिए? जैसे बिहार में जब कभी लालू यादव और उनके परिवार से जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी या सीबीआई पूछताछ करती है, तो लोग धरना-प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, वैसे ही क्या कांग्रेस ने भी वही मॉडल अपना लिया?

बंगाल हिंसा को लेकर ममता पर उठाए सवाल

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में हालिया हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हमलों को नजरअंदाज कर रही है। वक्फ बोर्ड में सुधारों पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी उन्होंने तंज कसा और जवाब मांगा।

बहरहाल ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से ही देश में राजनीति में गर्माहट साफ देखने को मिली है, जिसके चलते राजनीतिक वार और पलटवार वाले बयान भी तेजी आने शुरु हो गए हैं। इससे देश का राजनीतिक गलियारा और गरमाने की उम्मीद है।

अगर 4 सौ पार हो गई होतीं तो संविधान खत्म करने राइफल और तलवार लेकर निकलते : अखिलेश

लखनऊ। यदि भाजपा ने 400 सीट पर जीत दर्ज की होती तो सड़कों पर राइफलें और तलवारें लेकर निकले होते और संविधान खत्म हो गया होता। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में अराजकता चरम पर है। असामाजिक तत्व खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या यही कानून और संविधान का राज है। यदि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीती होती तो सड़कों पर राइफलें और तलवारें निकल चुकी होतीं और संविधान खत्म हो गया होता। ये दावा करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम भाजपा की असंवैधानिक कार्रवाई, अन्याय और अराजकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को भगवान और संविधान की आत्मा बताया।卐 यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर किसानों की परेशानी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भाजपा न्याय सुनिश्चित नहीं करना चाहती। यह पार्टी पीडीए के लिए आरक्षण के खिलाफ है। करणी सेना के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर दी गई धमकियों के जवाब में यादव ने कहा, 卐ये सभी भाजपा के लोग हैं। भाजपा के सैनिक। जिस दिन हमारी एनएसजी सुरक्षा केंद्र द्वारा हटाई गई, हमें उनकी मंशा पता चल गई। मैं डरूंगा नहीं। जिन्होंने एनएसजी सुरक्षा रखी है, वे कायर हैं। उन्हें भी अपनी एनएसजी सुरक्षा लौटा देनी चाहिए। राजशाही और इतिहास पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए यादव ने कहा, हम राजाओं के खिलाफ नहीं हैं। एक राजा की कोई जाति नहीं होती। वह बस राजा होता है। यदि इतिहास प्रगति, सामाजिक सौहार्द और एकता के रास्ते बाधा बने तो उसे छोड़ देना चाहिए।

कर्नाटक में सरकार के खिलाफ लिंगायत और वोक्कालिगा ने खोला मोर्चा

-जातिगत जनगणना रिपोर्ट को राजनीतिक प्रभाव के लिए मान रही खतरा

बेंगलुरु(एजेंसी)। कर्नाटक में दो प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और वोक्कालिगा राज्य की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के फैसले से दोनों समुदायों में गहरी नाराजगी है। वे इसे अपने राजनीतिक प्रभाव के लिए खतरा बता रहे हैं। सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर खुद कांग्रेस के विधायकों ने जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। 17 अप्रैल यानी गुरुवार को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति तय होगी, जिससे कई समुदायों की आगामी रणनीति प्रभावित हो सकती है। वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी ही पार्टी के वोक्कालिगा विधायकों से मुलाकात की और रिपोर्ट पर राय जानी। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर मैं चाहूंगा कि हम मिलकर कैबिनेट बैठक में अपने पक्ष को मजबूती से रखें। हालांकि उन्होंने अपने रुख को सार्वजनिक नहीं किया। लिंगायत-वोक्कालिगा की जनसंख्या हिस्सेदारी पर रार जाति सर्वेक्षण की आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन लिंगायत और वोक्कालिगा का हिस्सा राज्य की आबादी का एक चौथाई से भी कम है। लिंगायत और वोक्कालिगा की जनसंख्या हिस्सेदारी को लेकर यह संघर्ष कर्नाटक में कोई नई बात नहीं है।

कांग्रेस का मौजूदा सामाजिक गठबंधन लिंगायत और वोक्कालिगा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। पिछले कुछ सालों से एग्जिट पोल तेजी से गलत हो रहे हैं। 2023 के कर्नाटक चुनावों के लिए एग्जिट पोल ने कांग्रेस के वोट शेयर (43.2 फीसदी के मुकाबले 43 फीसदी) और सीटों (वास्तविक 135 के मुकाबले 122-140) की सटीक भविष्यवाणी की। एग्जिट पोल द्वारा दिए गए जाति-वार समर्थन संख्या से पता चलता है कि कांग्रेस का वोक्कालिगा और लिंगायतों के बीच 24-20 फीसदी वोट शेयर था। वोक्कालिगा का विरोध और चेतावनी वोक्कालिगा समुदाय की शीर्ष संस्था वोक्कालिगारा संघ ने मंगलवार को आपात बैठक कर राज्यव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई है। सत्ताधारी पार्टी के अंदर मतभेद उभरने लगे हैं, खासकर उन समुदायों से आने वाले नेताओं के बीच, जिनकी जनसंख्या आंकड़ों में घटी हुई दर्शाई गई है। कांग्रेस के पास कर्नाटक के सबसे सफल राजनीतिक गठबंधन को पुनर्जीवित करने का मौका है। कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक चुनावों में 60 फीसदी से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी।

आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाक को भारत की दो टूक कहा- हमे मत बताओ खुद का रिकॉर्ड देखो

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है कि वो अपने गिरेबान में तो झांकना नहीं है और बात-बात पर भारत को ज्ञान देने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसी कड़ी में हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से वक्फ कानून के विरोध में एक बयान जारी किया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए साफ-साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान में हिन्दू सहित अन्य अल्पसंख्यकों की हालात को देखे। भारत को पाठ पढ़ाने की जगह वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी कड़ी में वक्फ पर पाकिस्तान की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, 'हम भारत की संसद द्वारा पारित वक्फ कानून पर पाकिस्तान द्वारा

की गई प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने खुद के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। इससे पहले, पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मस्जिदों और दरगाहों सहित मुसलमानों को उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने वाला कानून करार दिया था। कहा गया था कि यह कानून भारतीय मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला कदम है। पाकिस्तानी मीडिया में मुस्लिम समाज की भूमि हड़पने और मुस्लिम संपत्तियों पर नियंत्रण का प्रयास करार दिया था। केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक मौजूदा बजट सत्र में पेश किया। इस दौरान लंबी चर्चा के बाद आधी रात को विधेयक पास किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा गया।

लोगों की सुरक्षा और एक्सीडेंट को रोकने गडकरी ने तैयार किया प्लान

-टू-व्हीलर के साथ 2 हेलमेट, रोड पर सब मैंडेटरी प्रीकास्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क पर लोगों की सुरक्षा और एक्सीडेंट को रोकने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में नए टू-व्हीलर के साथ 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। वहीं, अब रोड पर सब मेंडेटरी प्रीकास्ट होगा। उन्होंने कहा कि रोड अब फैक्टरी में बनेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि सिर्फ स्कूल के सामने हर साल 10 हजार बच्चे सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। इस रोकने के लिए उन्होंने बड़ी तैयार की है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जो भी टू-व्हीलर खरीदता है कंपनी ग्राहक को किसी अच्छी कंपनी के दो आईएसआई स्टैंडर्ड वाले हेलमेट भी देगी, ताकी गाड़ी पर चलने वाले दोनों लोग हेलमेट पहनें। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी में हम लंबे समय से काफी काम कर चुके हैं उसके बाद भी अभी सफलता नहीं मिल रही है। सिर्फ स्कूल के सामने ही हर साल 10 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। जबकि, हर साल 1 लाख 80 हजार मौत सड़क दुर्घटना में होती हैं। इसतरह हम रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं। ब्लैक स्पॉट का पता लगा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने एक राहवीर योजना भी तैयार की है। योजना में जिसका एक्सीडेंट होता है और घायल व्यक्ति लेकर कोई अस्पताल आता है और उसकी जान बचाता है। तब हम उस मददगार को 25 हजार रुपए का इनाम देने वाले है। साथ ही, जो अस्पताल में एडमिट होगा, उस अधिकतम 7 दिन का खर्च या 1.50 लाख रुपए की सहायता देने और उसकी जान बचाने की कोशिश की जाएगी। यदि लोग एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं तब हम हर साल 50 हजार लोगों की जान बचा सकते हैं।

गडकरी ने बताया कि अब रोड पर सब मेंडेटरी प्रीकास्ट होगा। यानी रोड अब फैक्टरी में बनेगा। अभी रोड के बीच में जो वैरियर होते हैं लोग उन्हें कूदकर आगे जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। इसतरह अब इन वैरिएट की ऊंचाई को 3 फीट तक बढ़ाया जाएगा। इसके दोनों तरफ एक मीटर की दूसरी रखी जाएगी जिसमें काली मिट्टी डालकर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके बाद कोई इन्हें कूदकर पार नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी लाए हैं जिससे हजारों-करोड़ रुपए बच रहे हैं।

भाजपा-संघ को परास्त करने का रास्ता गुजरात से निकलेगा : राहुल गांधी

अरवल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा पहुंचे, जहां उन्होंने अरवल्ली जिला कांग्रेस नेता के साथ बैठक की और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की शुरुआत गुजरात से हुई थी और भाजपा-संघ को परास्त करने का रास्ता भी गुजरात से निकलेगा। राहुल गांधी ने आज मोडासा से संगठन सृजन अभियान का भी शुभारंभ कराया। बता दें कि राहुल गांधी मंगलवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। बीते दिन राहुल गांधी ने अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) और 183 प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के पर्यवक्षकों के साथ बैठक की थी। साथ ही पर्यवेक्षकों से अगले 10 दिन सौंपे गए जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि संबंधित जिले के संगठन में बदलाव करते हुए नए जिला अध्यक्ष की नियुक्त की जा सके। कांग्रेस ने हर एक जिले के केंद्रीय निरीक्षक के साथ 4 गुजरात निरीक्षकों की टीम गठित

की है। गुजरात दौरे के दूसरे और अंतिम दिन अरवल्ली जिले के मोडासा में राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने मोडासा में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ कराया और अरवल्ली जिला कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और बूथस्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि संघ और भाजपा को देश में पराजित करने का रास्ता गुजरात से निकलेगा। देश में दो विचार धारा हैं। एक भाजपा-संघ और एक ही कांग्रेस। देश जानता है कि भाजपा-संघ को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरुआत गुजरात से हुई थी और यहीं से भाजपा-संघ को हराने का रास्ता भी मिलेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमारी चर्चा में जो मुख्य मुद्दा उभरकर आया वह यह था कि गुजरात के जिलों को अहमदाबाद से नहीं, बल्कि जिलों से ही चलाया जाना चाहिए। जिला नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, विशेषकर जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी और अधिकार देकर। जिला अध्यक्ष अकेला नहीं होगा बल्कि एक पूरी कमेटी होगी, जिसके सहयोग और निर्णयों से पूरे जिले का संचालन होगा और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी संगठन ही तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, और इस निर्णय में कोई दबाव नहीं होगा। हम यह काम गुजरात से शुरू कर रहे हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हम गुजरात में यह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी ने माना कि वर्षों से गुजरात में कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है, लेकिन अब हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे। पार्टी का मनोबल बढ़ाना मुश्किल नहीं है, हम उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब रेस के घोड़े को रेस में दौड़ाएंगे और शादी के घोडे को शादी में नचाएंगे।

क्या परिवार में मनमुटाव से बचने के लिए मायावती ने माफ किया आकाश आनंद को

बुधवार की बैठक में आनंद की गैरमौजूदगी से फिर उठे सवाल

लखनऊ (एजेंसी)। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के पीछे शादी को कारण बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश आनंद के भाई और मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आंनद की शादी 24 अप्रैल को हरियाणा में होनी है। शादी में मायावती भी शामिल होंगी। इसलिए परिवार में मनमुटाव की स्थिति से बचने के लिए आकाश की माफी वाली स्क्रिप्ट चर्चा में है। बुधवार को लखनऊ में हुई बसपा की समीक्षा बैठक में आकाश आनंद नहीं पहुंचे थे। इतना ही नहीं एक घंटे चली बैठक के बाद बसपा द्वारा जारी नोट में भी आकाश आनंद को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। जबकि बताया जा रहा था कि वापसी के बाद हो रही अहम बैठक में आकाश आनंद शामिल हो सकते हैं और उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। बताया जा रहा

हैं कि मायावती अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रही है। हो सकता है दिल्ली में भी आकाश और मायावती मुलाकात हो जाए।

सूत्रों ने बताया कि मायावती के भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार ने सुलह की पटकथा लिखी, क्योंकि ईशान की शादी में मनमुटाव वाला माहौल लोगों और मीडिया के सामने आए। क्योंकि शादी वाले घर में सभी को आमना सामना होगा। लिहाजा आकाश आनंद ने अपनी गलती को मानकर माफी मांग ली और कभी दुबारा ऐसी गलती न करने की बात कही। इसके बाद बुआ मायावती ने भी उन्हें माफ कर पार्टी में वापसी करा दी। लेकिन बुधवार को लखनऊ में हुई मीटिंग में आकाश आनंद की गैरमौजूदगी अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

उपद्रवियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी ममता सरकार, संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल: नकवी

-विक्टिमहुड का रिएक्शन देना, सस्ता राजनीतिक हथकंडा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ कानून को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। ममता सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को जानबुझकर दरकिनार कर रही हैं और उपद्रवियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं।

भाजपा नेता नकवी ने सीएम ममता संग इमामों की बैठक को लेकर कहा कि कुछ जगहों पर विशेषकर बंगाल में हिंसा हो रही है, जो चिंता का विषय है। ऐसा लगाता हैं कि ममता सरकार उन लोगों के हाथों बंधक बन चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार उन्हीं के सम्मेलन आयोजित करती है, तब सवाल उठता है कि वह भरोसे का संदेश देना चाहती है या भय का। बंगाल में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन इसका प्रमाण है कि वहां की संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है।

इतना ही नहीं नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर भी नकवी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुनबे की करतूतों को क्रांति का ताबूत बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है। यह जो कार्रवाई हो रही है, वह किसी राजनीतिक द्वेष का हिस्सा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर आधारित वैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट ने पहले ही इस पर निर्देश दिए हुए हैं।

नकवी ने कहा कि यह जो कपट है, इस पर न भाजपा की रपट है और न ही मोदी सरकार की कोई नई रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट पहले से मौजूद हैं और कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रही है।

कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को ड्रामा करार देकर भाजपा नेता ने कहा कि जो विधिक कार्रवाई है, उस पर विक्टिमहुड का रिएक्शन देना एक सस्ता राजनीतिक हथकंडा है। देश की जनता सब जानती है और अब वह इस तरह के ड्रामों में नहीं आने वाली।

धनुष की इन आगामी फिल्मों में दिखेगा जबरदस्त एक्शन और रोमांस

इटली कड़ाई और कुबेर में धनुष अलग-अलग किरदारों में नजर आएंगे, वहीं डी55 और डी56 उनके फैंस के लिए बड़े सरप्राइज हो सकता है। इसके अलावा, तेरे इश्क में एक रोमांटिक फिल्म होगी, जिसमें धनुष का नया अंदाज देखने को मिलेगा। फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इटली कड़ाई

इटली कड़ाई एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसे धनुष खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें नित्या मेनन भी नजर आएंगी। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। फिल्म में धनुष और अरुण विजय मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इडली कढ़ाई का संगीत प्रसिद्ध जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है।

कुबेर

कुबेर एक अलग अंदाज की फिल्म है, जो जून 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन शेखर कम्मुला ने किया है। फिल्म में धनुष के अलावा रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण पुष्कर राम मोहन राव, नारायण दास कर रहे हैं।

तेरे इश्क में

तेरे इश्क में एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसकी झलक फैंस को पहले ही पसंद आ चुकी है। इस फिल्म में धनुष के साथ पहली बार कृति सेनन की जोड़ी नजर आने वाली है। फिल्म की झलक देखने के बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

डी55

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ष्ठ55 एक ड्रामा तमिल फिल्म है, जिसका निर्देशन राजकुमार पेरियासामी कर रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट में धनुष मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। डी55 फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।

साउथ के बारे में चाहत खन्ना का चौंकाने वाला खुलासा

एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने हाल ही में साउथ इंडस्ट्री के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का काला चिट्ठा खोलते हुए कहा है कि वहां कॉन्ट्रैक्ट में साफ-साफ लिखा होता है कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। चाहत खन्ना ने इस बात का खुलासा हाउटरफ्लाई के साथ बातचीत के दौरान किया। एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर खुलासा करते हुए बताया कि वहां काम करने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज के बारे में पूछ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सारी चीजें वहां सरेआम होती हैं। कान्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ऐसी बातें आपस में हो ही जाती है। कान्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा।

चाहत खन्ना ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड में भी ऐसा होता है, लेकिन यहां के तरीके कुछ अलग है। यहां अलग तरीके से एक्ट्रेस से पूछा जाता है। जब भी कोई नया एक्टर आता है तो उन्हें इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चाहत खन्ना कहती है कि उनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहत खन्ना अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बचपन में मोलेस्ट किया जा चुका है। एक्ट्रेस ने कहा था- जब मैं बहुत छोटी थी, तब एक अंकल अपनी गोद में बिठाकर चॉकलेट देते हैं। तब इतनी समझ नहीं थी, दो साल साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ मेरे साथ क्या हुआ था। चाहत खन्ना अब कम ही छोटे पर्दे पर नजर आती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। उन्होंने इंडस्ट्री में तलाक को लेकर बन चुकी सोच को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं।

बता दें कि एक्ट्रेस का दो बार तलाक हो चुका है। उनकी पहली शादी ज्यादा लंबी नहीं चली थी। महज 4 महीने के अंदर ही उन्होंने तलाक ले लिया था। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और दोबारा शादी की, लेकिन वह शादी भी लंबे समय तक नहीं चली और तलाक हो गया। चाहत कहती हैं कि तलाक और सेपरेशन कभी भी आसान नहीं होते, खासकर तब जब बच्चे हों। उन्होंने आगे कहा- मेरा दूसरा तलाक बहुत मुश्किल था। मेरी एक बेटी फरहान के साथ रहती है और एक मेरे साथ रहती है।

क्या बिपाशा बसु फिल्म 'रेस 4 का हिस्सा बनेंगी?

बिपाशा बसु फिल्म 'रेस (2008)' में सैफ अली खान के अपोजिट नजर आईं। हाल ही में 'रेस 4' को लेकर काफी चर्चा रही। इसी बीच बिपाशा ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट की। इस पोस्ट के जरिए आखिर बिपाशा क्या बताना चाहती हैं? क्या वह भी फिल्म 'रेस 4' का हिस्सा हैं?

बिपाशा बसु ने हाल ही में इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में फिल्म 'रेस' का गाना 'रेस सांसों कीज' को साझा किया। इस गाने में वह डांस कर रही हैं, साथ ही कैटरीना कैफ भी इसमें नजर आ रही हैं। इस गाने को बिपाशा एक बार फिर से क्यों याद कर रही हैं? इसको लेकर बिपाशा ने कोई भी कैप्शन या मैसेज नहीं लिखा है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म 'रेस 4' के मेकर्स को हिंट देना चाहती हैं। क्या एक्ट्रेस दोबारा से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं?

सोनिया का किरदार निभाया था

फिल्म 'रेस (2008)' में बिपाशा बसु ने सोनिया का किरदार निभाया था। फिल्म में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर नजर आए थे। हाल ही में खबर थी 'रेस 4' में एक नई एंट्री होने वाली है। मेकर्स ने भी कंफर्म किया कि फिल्म में सैफ अली खान के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। बाकी किसी दूसरे एक्टर के नाम पर फिल्म मेकर्स ने मुहर नहीं लगाई है।

बिपाशा लंबे वक्त से ब्रेक पर हैं

बिपाशा बसु की बात की जाए तो वह करण ग्रोवर के साथ शादी करने के बाद से ही फिल्मों में कम नजर आने लगी हैं। बेटी देवी के जन्म के बाद तो वह फिल्मों में दिखीं ही नहीं। हो सकता है कि फिल्म 'रेस' का गाना शेयर कर, बिपाशा फिर से फिल्मों में वापसी की चाहत रख रही हों।

ग्लैमरस किरदारों के लिए जानी गईं बिपाशा

बिपाशा बसु ने अपने करियर में 'अजनबी', 'राज', 'जिस्म' अलोन, नो एंट्री, फुटपाथ, अपहरण, बचना ए हसीनों जैसे कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मा में अभिनय किया है। अधिकतर फिल्मों में उनका ग्लैमरस अंदाज ही नजर आया, जिसे दर्शकों ने पसंद भी किया।

रिद्धिमा कपूर के साथ पर्दे पर नजर आएंगे कपिल शर्मा

कपिल शर्मा इन दिनों अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब उनके वजट घटाने के पीछे की कहानी भी पता चल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने अपनी आगामी फिल्म के लिए अपना वजन घटाया है। खास बात यह है कि इस फिल्म रिद्धिमा कपूर साहनी भी नजर आने वाली हैं। फिल्म का निर्देशन आशीष आर मोहन करेंगे। फिलहाल फिल्म का नाम अभी तय नहीं हो सका है। आने वाले समय में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा की उम्मीद की जा रही है।

फिर हेरा फेरी से लेकर हाउसफुल 2 तक, इन फिल्म दूसरे भाग में छाए अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्में हर बार उनके फैंस के दिलों पर छा जाती हैं। वह ऐसी कई सीक्वल फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म केसरी का दूसरा चैप्टर जल्द ही दर्शकों के लिए रिलीज होने जा रहा है।

हाउसफुल 2

जब बात कॉमेडी की आती है तो हाउसफुल 2 का जिक्र जरूरी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने जबरदस्त अभिनय किया था, जो गलतफहमियों और मजेदार सिचुएशन्स में फंसता चला जाता है। अक्षय के साथ रितेश देशमुख, जॉन अब्राहम भी फिल्म में नजर आए थे।

फिर हेरा फेरी

फिर हेरा फेरी तो हर कॉमेडी प्रेमी की फेवरेट लिस्ट में शुमार है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने राजू का किरदार निभाया था जो अपने दोस्तों श्याम (सुनील शेट्टी) और बाबूराव (परेश रावल) के साथ पैसा कमाने के चक्कर में उलझ जाता है। इन तीनों की तिकड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि फिल्म के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं।

ओएमजी 2

ओएमजी 2 में अक्षय कुमार ने एक अलग ही अंदाज में दर्शकों का दिल जीता था। इस फिल्म में उन्होंने भगवान शिव के दूत का किरदार निभाया था, जो एक आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाता है। फिल्म ने शिक्षा और धर्म जैसे गंभीर मुद्दों पर बात की गई है, लेकिन इसे इतने सहज और मनोरंजक तरीके से पेश किया गया कि हर कोई इससे जुड़ गया।

जॉली एलएलबी 2

जॉली एलएलबी 2 में अक्षय ने वकील जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली का किरदार निभाया था। फिल्म में उसकी जिंदगी में आने वाला एक केस उसे कानूनी व्यवस्था की खामियों से रूबरू कराता है। अक्षय ने इस किरदार को इतने हल्के-फुल्के अंदाज में निभाया कि दर्शक हंसते-हंसते गंभीर मुद्दों को भी समझ गए।

हमारे परिवार के साथ और भी बुरा हो सकता था, पर अब हम अलर्ट हैं

रंग दे बसंती, आहिस्ता आहिस्ता, खोया खोया चांद और साहब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों और कौन बनेगी शिखरवती और हश हश जैसी वेब सीरीज में नजर आने वाली सोहा अली खान को अपने फिल्मी खानदान से परे अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, मगर आखिरकार उन्होंने अपनी जमीन पुख्ता की। इन दिनों वह चर्चा में हैं हॉरर फिल्म छोरी 2 को लेकर, जिसमें वह हॉरर रोल में हैं। इस मुलकात में उन्होंने अपनी फिल्म, भाई सैफ अली खान पर हुए अटैक, मदरहुड, सोशल मीडिया और हॉरर जॉनर जैसे कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी।

सोहा पिछले दिनों आपके परिवार के साथ जो हादसा हुआ, उसने आप लोग को और ज्यादा अलर्ट हुए? क्या प्रभाव पड़ा?

सोहा अली खान बोलीं-अलर्ट तो हम हैं ही। मेरा मानना है कि कभी -कभी दुर्भाग्य से ऐसी चीजें हो जाती हैं। बस यही कामना करती हूं कि और ज्यादा बुरा नहीं हुआ। इससे बुरा भी हो सकता था। जो कुछ हुआ एक हद तक हुआ, तो इसके लिए हम खुशकिस्मत महसूस करते हैं। सब ठीक है। शुक्रगुजार हैं कि वो काम पर लौट आए हैं।

आप सात साल की बेटी इनाया की मां हैं। आप मदरहुड और काम के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती हैं?

आप देख ही रही हैं कि इस जूम इंटरव्यू में मुझे अपने डॉग को भी संभालना पड़ रहा है। आपने जूम इंटरव्यू के दौरान देखा कि कैसे बेल बजने पर वो भौंक रहा है। घर पर कोई नहीं है। देखिए हम सभी महिलाएं बहुत कुछ करती हैं, मगर साथ ही ये स्वीकार करना होगा कि हम सब महिलाएं एक समय में सबको सब कुछ नहीं दे सकतीं। कई बार हम उतनी परफेक्ट नहीं हो पातीं। मुझे याद है, एक सीन की शूटिंग के दौरान मेरी बेटी इनाया को काफी तेज बुखार हो गया था। मैं सफेद लेंसेज पहन रही थी और डॉक्टर के मेसेजेस आ रहे थे, मगर उन्हें पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि सफेद लेंस पहनने के बाद आपको दिखता नहीं है। मैं उसे वक्त डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे लिए बहुत ही तनावपूर्ण था।

क्या ये सच है कि अपनी फिल्म के भयानक हॉरर गेटअप के कारण आप अपनी बेटी इनाया से दूर रहीं और आपके पति कुणाल खेमू (अभिनेता - निर्देशक) भी आपसे दूर-दूर रहे?

मैंने अपने ऐसे बहुत सारे विडियोज लिए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुणाल खेमू मेरा कॉल नहीं ले रहे हैं (हंसती हैं) मेरा जब मेकअप उतर जाता, उसी के बाद कुणाल मुझसे बात करते थे। इनाया का जब सोने का समय होता था, तो मैं फिल्म छोरी 2 की शूटिंग से उसे हमेशा विडियो कॉल करती हूं। यह मेरा रूटीन है। मगर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं उसे विडियो कॉल नहीं कर पाती थी, फेस टाइम नहीं कर पाती थी। वो मासूम मुझसे पूछती मम्मा, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही हो, तब मुझे उसे बताना पड़ा कि इस फिल्म में मेरा मेकअप अलग है और मैं एक इविल किरदार निभा रही हूं। वो किताबें पढ़ती हैं और उन्हें गुड और इविल के बारे में जानकारी है, मगर वो बहुत ही जिज्ञासु हो गई, तब एक दिन मुझे उसे अपना गेटअप दिखाना पड़ा। अब तो मेरी इस फिल्म की एक होर्डिंग इनाया के बैडरूम की खिड़की के बाहर ही लगा हुआ है।

आज सोशल मीडिया हमारे लिए जरूरी भी है, मगर साथ ही ये कई बार हमारे साथ -साथ हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक भी होता जा रहा है, आप अपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करती हैं?

मैं अपने सोशल मीडिया को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेती हूं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर 24 घंटे रहते हैं, मेरी पास वो समय नहीं होता। मैं एक व्यक्ति के रूप में भी काफी अनुशासित हूं, तो मैं इस माध्यम एक इस्तेमाल कभी अपने काम को प्रमोट, अपना एंडोर्समेंट साझा या फिर अपनी निजी बात को शेयर करने के लिए करती हूं। मैं ये भी समझती हूं कि इंस्टाग्राम पर सब कुछ रियल नहीं होता। लोग अच्छी-अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं, बुरी चीजें शेयर नहीं करते, मगर मैं लोगों को जज नहीं करती। हां, लोग मुझे जज करते हैं। कई बार बुरे-बुरे कमेंट्स करते हैं, अजीब किस्म की बातें लिखते हैं, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।

क्या आप मानती हैं कि बीते सालों में फिल्मों में जो हॉरर का जो स्पेस है, वो री डिफाइन हुआ है? पहले हॉरर छुपकर देखना पड़ता था, अब परिवार के साथ देख सकते हैं?

मैंने आज तक इतना हॉरर कन्ज्यूम नहीं किया है। मैं हॉरर काम देखती हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि हॉरर शायद परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता। मैं हॉरर को हॉरेक्स (हॉरर और सेक्स का मिश्रण) जॉनर में सोचा करती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बनूंगी और डरावनी फिल्म में भूतिया रोल प्ले करूंगी। हमारी फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम का इंटेंशन यही था कि हम इसे इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अमृता आर पंडित द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी- 868, न्यू अशोक नगर दिल्ली 110096 से मुद्रित तथा ए-115, गली नंबर 13, नई अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित।
संपादक - अमृता आर पंडित, मो 8587969284, Mail ID - live18newsnetworktv@gmail.com सभी विवादों के न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय में होगा।